



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

5.1.4 The institution adopts the following for redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

DVV Suggestion:-

1. HEI is requested to kindly note that the link provided in the attached documents is in the GOOGLE DRIVE format, which should not be considered. Please relook and provide valid link for documents in correct format or could host these documents on HEI's website.

HEI Reply:-

- DVV suggestion is accepted. Valid link for documents in correct format is provided and also hosted these documents on HEI's website.**

<https://vim.org.in/pdf/5.1.4%20The%20institution%20adopts%20the%20following%20for%20redressal%20of%20student%20grievances%20including%20sexual%20harassment%20and%20ragging%20cases-compressed.pdf>



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

DVV Suggestion:-

2. Please provide Proof of constitution of Internal committees / Grievances Committee formation / other committees as per UGC norms.

HEI Reply:-

- The gazette of UGC norms for the constitution of Internal committees / Grievances Committee formation / other committees is attached.



I/C DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa Dist. Sangli.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है. नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में-बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

(अ) "पीडित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला-चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं सनाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैंटीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो-जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

2136 GI/2016





I/C DIRECTOR

Venkateshvara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु-अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है—यह समस्त उक्त परिचर में सम्मिलित हैं;

- (डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है;
- (ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत का दायर करना—अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;
- (एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उक्त व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से पशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन-सहायक शोध-सहायक चाहे वे रोजगार में हैं अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;
- (जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हैं— तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवाओं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;
- (एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचई.आई.) से अर्थ है—एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;
- (आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्त, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केंद्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्त कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;


- (जे) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कामूतों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है— जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न मामलों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमे में बतौर गवाह मौजूद रहना;

- (क) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है—

- (1) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अस्पष्ट मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और घमकी भय वातावरण पैदा करती हैं अथवा चरमक अथवा घमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर धरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः—

- (अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अत्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण
- (ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना
- (स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना




 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tal. Wajwa, Dist. Sangli.

- (इ) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पारा बने रहने की कोशिश करना
- (ई) अश्लील साहित्य दिखाना
- (ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं—
- (अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में है;
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;
- (स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;
- (द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;
- (ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;
- (एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हः
- बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है— यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:
- बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;
- (एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है—बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;
- (ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:
- (अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।
3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व—(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)
- (अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना,
- (ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना;



S/L
VC DIRECTOR
 Vankateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

- (स) जैसा कि आयोग की "सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम) रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुगम बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित बनाना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;
- (द) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;
- (एफ) सभी स्तरों पर अपने परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;
- (जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है— तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;
- (एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नॉटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी सनुदायों के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी लक्ष्य के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेन्डर सेन्सिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हार्समेंट—जी.एस.सी. ए.एस.एच. निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटी—आई.सी.सी.) के समान ही पुनर्गठित करना;
- गर्भों, बाद में दर्शाये गए मामलों में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा:
- (आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;
- (जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- (के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से गतिशील बनाना चाहें वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो;
- (एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना अथवा विधि द्वारा मान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अपरोध हेतु तन्त्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;
- (एम) यदि उस दुराचार का षडयंत्रकारी वहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;
- (एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्मक नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;
- (ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;
- (पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;
- (क्व) एक जार्विक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, यह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ—

- (1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र (आई.सी.सी.) प्रकाशित करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय-समय पर संशोधित किया




 Venkateshwar Institute of Management
 Path, Tal. Wahwa, Dist. Sangli.

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुरार अधिनियम लागू किया जाना है,

- (2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकाशित के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आवंटन भी हो;
- (3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से सामर्थ्य से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है;
- (4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध संरक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं;
- (5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अग्रिमूखी एवं पुनरुत्थान पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;
- (7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;
- (8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए;
- (9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार ये स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है;
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए;
- (11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से ये स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शान के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए;
- (12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है;



I/C DIRECTOR

Venkateshvara Institute of Management
Path, Tal. Warwa, Dist. Sangli.

- (13) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभाव पूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियां जो महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना— विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए;
- (14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होनी अविदेशात्मक हैं। महिलाओं के दिग्घ्न में इस प्रक्रिया में लिंग संबंधी डाक्टर और नर्सों तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए;
- (15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ पुनः चालू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही ये आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियाँ विस्तारित करेंगी जिनमें लैंगिक संबंधीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगी। "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल" इन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि ये कार्यशालाएँ नवोन्मेषी, आकर्षक बनें एवं नशीली न हों;
- (16) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्य, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जवाबदेही के दायरे में यथाआवश्यक रूप से लाना चाहिए;

4. शिकायत समाधान तन्त्र—

- (1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदाकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी. की निम्न संरचना होगी:—
- (अ) एक पीटासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर (एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह-प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- बशर्त यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीटासीन अधिकारी को उप-अनुभाग 2(अ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगा;
- "बशर्त यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियुक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"
- (ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर-अध्यापनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए;
- (स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकस्तर एवं स्नातकस्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;
- (द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी संघ में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- (2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए;
- (3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, पदम कुलपति, रक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसी केन्द्र के प्रकार्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे;



Sd/-
VC DIRECTOR
 Venkateshvara Institute of Management
 Peth, Tal. Wahwa, Dist. Sangli.

- (4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केंद्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;
- (5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है;
- (6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि—
- (अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
- (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा
- (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी संवामें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;
- तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;"

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :- आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
- (ब) विवाद समाधान के हेतु वातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मंत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े,
- (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अयकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा,
- (द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
- (ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्यवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

6. शिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:- आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह सन्तुष्ट रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे,

7. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :- किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें,

वर्शते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा,

वर्शते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर सन्तुष्ट सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:-




VC DIRECTOR
 Venkateswara Institute of Management
 Path, Tal. West, Dist. Sangli.

- (1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी,
- (2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पत्तों के नामों एवं उनके पत्तों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा,
- (3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जाँच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि व हों, तो, जाँच पड़ताल रिपोर्ट उस जाँच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जाँच के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी;
- (4) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जाँच के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो;
- (5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों/अनुशंसाओं के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है,
- (6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है— उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही करेंगे;
- (7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होगा चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथार्थि उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलन कराएगा। किसी भी दण्डात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है;
- (8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जाँच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा;
9. आन्तरिक समाधान— उच्चतर शैक्षिक संस्थान,
- (अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जाखिम कम से कम बना रहे;
- (ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हित लाभों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश रक्षित कर दे,
- (ग) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें;
- (द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धनकी है तो उनका परिस्तर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे;
- (इ) शैक्षिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए;
10. दण्ड एवं हरजाना—
- (1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;
- (2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए— यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थान—
- (अ) ऐसे छात्र के विनोधाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे—पुस्तकालय, सभागार, आवासीय अगारों, गतागता, छात्रसंघ, भत्ते एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना;



Sd/-
VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tel. Wadwa. Dist. Sangli.

- (व) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश रशमित अथवा बाधित करना.
- (ख) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी.
- (ग) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना.
- (3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी बसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा—
- (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;
- (ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;
- (स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;
- (द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
- (ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किरतों में किए जाने का औचित्य.

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाई:-

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य, धे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार राजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए.

12. गैर अनुपालन के परिणाम:-

- (1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक विन्दुओं पर कार्यवाई करेगा—
- (अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;
- (ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;
- (स) संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को चोक देना;
- (द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;
- (ई) जन साधारण को, एवं राजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त नीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अथवा जवसमतंदवम चवसपवलद का समर्थन नहीं करता है;
- (एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्यक् विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्यद्धता को आहरित करने की अनुशंसा के लिये करें




MC DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

- (जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आह्वरण की अनुमति करना,
- (एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आह्वारित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथाचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;
- (जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन—III/4/असा/53]

जसपाल एस. संघु, सचिव, यूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent,
 - (b) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
 - (c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;




 VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Path, Tel. Warwa, Dist. Sangli.

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASIH)) should be reconstituted as the ICC:
- Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) "sexual harassment" means-
- (i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;-
- (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
- (b) demand or request for sexual favours;
- (c) making sexually coloured remarks
- (d) physical contact and advances; or
- (e) showing pornography"
- (ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
- (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
- (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
- (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
- (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;




I/C DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Waiwada, Dist. Sangli.

- (l) "student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI;
 Provided that a student who is in the process of taking admission in HEI's campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student;
 Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;
- (m) "third Party Harassment" refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose or reason;
- (n) "victimisation" means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;
- (o) "workplace" means the campus of a HEI including-
- Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;
 - Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;
 - Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIs.

3. **Responsibilities of the Higher Educational Institution- (1)** Every HEI shall,-

- Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;
- publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure their wide dissemination;
- organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;
- act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
- publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
- reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
- create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
- include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual




VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tel. W. Dist. Sangli.

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC; Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 Supportive measures.—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.



[Signature]
Venkateswara Institute of Management
Peth, Tal. Wadwa, Dist. Sangli.

(6) All Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCs) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.

(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.

(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.

(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.

(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.

(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.

(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women's hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.

(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.

(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.

(15) The Women's Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.

(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendments in the rules or Ordinances where necessary.

4. Grievance redressal mechanism.—(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-



SV
VC DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tel. Wadga, Dist. Sangli.

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;"

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
- (2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
- (3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice- Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
- (4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
- (5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
- (6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
- contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
 - has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
 - he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
 - has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section."

5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) - The Internal Complaints Committee shall:
- (a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;



SV
VC DIRECTOR
Venkateshwar Institute of Management
Peth, Tel. Mohad, Dist. Sangli.

- (b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
- (c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender,
- (d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
- (e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.

6. **The process for making complaint and conducting Inquiry** - The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy

7. **Process of making complaint of sexual harassment** - An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing:

Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period."

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental incapacity or death.

8. **Process of conducting Inquiry-** (1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.

(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.

(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.

(4) The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.

(5) An appeal against the findings or recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.

(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.

(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the




ICC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management,
 Peth, Tal. Wajra, Dist. Solapur

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. **Interim redressal**-The HEI may,

- (a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
- (b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
- (c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
- (d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
- (e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. **Punishment and compensation**- (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may:-

- (a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - (b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - (c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - (d) award reformatory punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
- (3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
- (a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - (b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - (c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - (d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - (e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. **Action against frivolous complaint**.—To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)




I/C DIRECTOR
 Venkateswara Institute of Management
 Peth, Tel. Warr. Dist. Sangli

of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

12. **Consequences of non-compliance.**—(1) The Commission shall, in respect of any institution that will fully contravenes or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice: -

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956.
- (b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (1) of section 2 of said Act, 1956;
- (c) withholding any grant allocated to the institution;
- (d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;
- (e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;
- (f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;
- (h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act.
- (i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations.
- (2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

[Advt -III/4/Exty/53]

JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC



VC DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Wadga, Dist. Sangli.



DTE CODE - MB6224

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Grievance Redressal Cell

As per the Maharashtra Public University Act, 2016 of the State Government and as per the notices and office orders issued by the Shivaji University, Kolhapur, the college has established the Grievance and Redressal Cell. Before the Grievance and Redressal Cell, there was a Grievance and Redressal Committee which was formed at the beginning of every academic year and ensures the representation of all the stakeholders of the institute. As the College Management and the Administration strongly believes in Gandhian Philosophy of Education, they ensure a secular, all-inclusive and secure atmosphere on the campus. Grievance and Redressal Cell conducts a mechanism of grievance redressal of students and prevention of sexual harassment and ragging of students. At the beginning of every academic year a meeting of staff and students were conducted by the Director to make the new students acquainted with the mechanism.

Grievance Redressal Committee objectives

- 1) The primary objective of the GRC is to ensure a fair and impartial resolution of grievances. It is responsible for examining complaints without bias and providing equitable solutions.
- 2) The committee aims to promptly address and resolve grievances raised by employees, customers, clients, or any other stakeholders related to the organization's operations.
- 3) One of the key objectives is to mediate and resolve conflicts or disputes that may arise between different parties involved with the organization.
- 4) The GRC ensures that the organization complies with all applicable laws, regulations, and internal policies related to grievance handling.

Function of Grievance Redressal Cell:

The functional mechanism of working of Grievance Redressal Cell is as the prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012 and Maharashtra Public University



IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



DTE CODE - MB6224

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Act, 2016 as it came in force. All the rules and regulations prescribed by the competent authority will be followed.

Jurisdiction of Grievance Redressal Cell

- a) The complaints regarding the admission and fees
- b) The complaints regarding the ragging and sexual harassment (the separate mechanism for these issues is also in force, but in the grave event handed over to the cell)
- c) The complaints regarding the academic and administrative processes
- d) The complaint against any staff member regarding academic and personal issues
- e) The complaints regarding examinations, results and scholarship

Mechanism of Grievance Redressal Cell:

- a) The grievances can be filed orally and in a written format to the Director or if the aggrieved student wants to keep his identity secret, he/she can put his complaint through the blind Complaint/Suggestion Box kept outside the Office.
- b) The Complaints registered directly to the Director is noted down in a separate complaint lodge book, which is kept in the custody of the Subrident of the office.
- c) The Complaint/Suggestion box is opened in the presence of any one member of the Cell and then registered in the complaint lodge book.
- d) After the judicious inquiry and statements from both the parties and the teachers and other related persons, the Grievance Cell will assure that the grievance has been properly solved in a stipulated time limit.
- e) The complaints that require the attention of the higher authorities and local police station, will be addressed only with their help.




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Grievance Redressal Committee**Academic Year 2020 -21 to 2021-22****Notice**

I am pleased to inform you that the College/Student's Grievance and Redressal Committee (Cell) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 (clause 56 (2)A), and the UGC Notification in Gazette of India on 6 May, 2019 (the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019), Clause S (1). Members of the committee are as follows From the today's date, next two years the committee will be in force

Sr. No	Members	Designation
1	Mr. Rahul N. Mahadik	Chairman
2	Dr. S.B Wadkar	Member Secretary
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Dr. A.M kharat	Faculty Member
5	Mr. A. S. Patil	Faculty Member
6	Mr. S. R jadhav	Non -Teaching Member



Sd/
I/C DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110



Grievance Redressal Committee

Academic Year 2017 -18 to 2019-20

Notice

I am pleased to inform you that the College/Student's Grievance and Redressal Committee (Cell) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 (clause 56 (2)A), and the UGC Notification in Gazette of India on 6 May, 2016 (the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019), Clause S (1). Members of the committee are as follows From the 2017-18 – 2019-20

Sr. No	Members	Designation
1	Mr. Rahul N. Mahadik	Chairman
2	Dr. P. K. Katti	Member Secretary
3	Dr. S.B Wadkar	Faculty Member
4	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
5	Dr. A.M kharat	Faculty Member
6	Mr. S. R jadhav	Non –Teaching Member



SJ
I/C DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaints Committee

The Internal Complaints Committee (ICC) is an essential entity established in organizations to address and resolve complaints related to sexual harassment at the workplace. Its primary objectives are to create a safe and respectful work environment for all employees, regardless of gender, and to ensure that any complaints of harassment are promptly and fairly dealt with. Here are the main objectives of an Internal Complaints Committee.

As per the guidelines of Supreme Court, UGC, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been established by the College for a period of five years (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22). A victim of sexual harassment has two courses open in having her grievance redressed. She can either give a complaint to the Internal Complaints Committee or give a police complaint relating to the penal offence.

Preamble

The Parliament of India passed the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act," in the year 2013. The ACT provides protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for the matters connected therewith or incidental thereto. The guidelines explicitly state the following: "It shall be the duty of the employer or other responsible persons in workplaces or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolutions, settlement, or prosecution of acts, of sexual harassment by taking all steps require."

Educational institutions are also bound by the Supreme Court's directive and the Act. The International Institute for Population Sciences (IPS), Mumbai is committed to creating and maintaining an environment which is free of all forms of gender violence, sexual harassment, and discrimination on the basis of sex/gender. Following this, the institute is "Internal Complaint Committee to Prevent Sexual Harassment of Women at the Workplace.



Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tst. Walva, Dist. Sangli.

Objectives of Internal Complaints Committee:-

- 1) The primary objective of the ICC is to prevent incidents of sexual harassment within the workplace. By implementing policies and guidelines, conducting awareness programs, and providing training to employees, the ICC aims to create a safe and harassment-free environment.
- 2) The ICC acts as a confidential and safe platform for employees/students to report any incidents of sexual harassment they may experience or witness. It ensures that complainants are not victimized or subjected to retaliation for reporting such incidents.
- 3) One of the core responsibilities of the ICC is to investigate complaints of sexual harassment thoroughly and impartially. The committee is entrusted with gathering evidence, interviewing witnesses, and making recommendations based on the findings of the investigation.
- 4) The ICC aims to resolve complaints of sexual harassment promptly and fairly. This includes providing a fair hearing to both the complainant and the accused, and ensuring that due process is followed throughout the proceedings.

The Definition of Sexual Harassment

According to THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT 2013, sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:

1. Physical contact and advances;
2. A demand or request for sexual favours;
3. Making sexually colored remarks;
4. Showing pornography,
5. Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Sexual harassment and punishment for sexual harassment

A man committing any of the following acts-

Physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures: or a demand or request for sexual favours, or showing pornography against the will of a woman or making sexually coloured remarks, shall be guilty of the offence of sexual harassment.




ICC DIRECTOR
Venkateshvara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwra Dist. Sangli.

Any man who commits the offence specified in clause (3) or clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both.

Prevention of sexual harassment (Section 3):

(1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace:-

(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment

- (i) Implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or
- (ii) Implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment or
- (iii) Implied or explicit threat about her present or future employment status; or
- (iv) Interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, or
- (v) Humiliating treatment likely to affect her health or safety.

In the event the Committee finds that the allegation(s) against the respondent have been proved, it shall recommend the nature of action to be taken by the Institute.

Internal Complaints Committee (ICC):

An aggrieved woman can send a written complaint to the Director of the Venkateshwara Institute of Management, Peth. The said complaint shall be forwarded to the Internal Complaints Committee (ICC) for an inquiry.

This committee has been formed at Venkateshwara Institute of Management, Peth, to address issues under THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013. The purpose of this committee is to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding five years, from the date of nomination.




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Wankar, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Internal Complaints Committee (ICC)

Academic Year 2021-22

Notice

I am pleased to inform you that the Internal Complaints Committee (ICC) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 2nd May, 2016 (University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015), Clause-4, 1(a,b,c,d) and 2. Members of the committee are as follows in academic year 2021-22

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. S.B. Wadkar	Chairman
2	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
3	Mr. A. S. Patil	Faculty Member
4	Miss. S.V Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D Patil	Advocate
6	Dr. S.B Shete	Social Worker
7	Miss. P. J. Kadam	Student


ICC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth Naka, Tal. Walwa, Dist. Sangli.





SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Internal Complaints Committee (ICC)**Academic Year 2020-21****Notice**

I am pleased to inform you that the Internal Complaints Committee (ICC) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 2nd May, 2016 (University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015), Clause-4, 1(a,b,c,d) and 2. Members of the committee are as follows in academic year 2020-21

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. S.B. Wadkar	Chairman
2	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
3	Dr. A. M Kharat	Faculty Member
4	Miss. S.V Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D Patil	Advocate
6	Dr. S.B Shete	Social Worker
7	Miss. J. V Patil	Student



S. V. Patil
Director
ICC DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Internal Complaints Committee (ICC)**Academic Year 2019-20****Notice**

I am pleased to inform you that the Internal Complaints Committee (ICC) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 2nd May, 2016 (University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015), Clause-4, 1(a,b,c,d) and 2. Members of the committee are as follows in academic year 2019-20.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P.K. Katti	Chairman
2	Dr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S.V Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D Patil	Advocate
6	Dr. S.B Shete	Social Worker
7	Miss. V.S Deshmukh Patil	Student



VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Internal Complaints Committee (ICC)

Academic Year 2018-19

Notice

I am pleased to inform you that the Internal Complaints Committee (ICC) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 2nd May, 2016 (University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015), Clause-4, 1(a,b,c,d) and 2. Members of the committee are as follows in academic year 2018-19

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P.K. Katti	Chairman
2	Mr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S.V Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D Patil	Advocate
6	Dr. S.B Shete	Social Worker
7	Miss. D.V. Kamble	Student




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110



Internal Complaints Committee (ICC)

Academic Year 2017-18

Notice

I am pleased to inform you that the Internal Complaints Committee (ICC) is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 2nd May, 2016 (University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015), Clause-4, 1(a,b,c,d) and 2. Members of the committee are as follows in academic year 2017-18.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P.K. Katti	Chairman
2	Mr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S.V Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D Patil	Advocate
6	Dr. S.B Shete	Social Worker
7	Miss. P. A. Kadam	Student



Suj
 UC DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee

Introduction

The College has constituted the Anti-Ragging Committee in the year 2012-13. The following instructions are framed to prevent the menace of ragging and foster healthy interpersonal relations among students in the campus of Venkateshwara Institute of Management Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. All students shall familiarize themselves with rules/regulations/guidelines on code of conduct anti-ragging measures and discipline College. All 'new comers' should attend counseling sessions organized for them from time to time by the college staff.

Objectives:-

- 1) The committee works to prevent ragging incidents from occurring in the first place. It raises awareness among students about the consequences of ragging and the college's strict stance against it.
- 2) The committee educates students about the negative impacts of ragging on victims' mental and emotional well-being, as well as the legal implications for those involved in ragging incidents.
- 3) The committee develops clear and comprehensive anti-ragging policies and guidelines that outline what constitutes ragging, the penalties for engaging in it, and the reporting mechanisms.
- 4) Upon receiving reports of ragging or any related incidents, the committee takes prompt action to investigate the matter thoroughly. It ensures that disciplinary actions are taken against those found guilty, in accordance with the college's policies.



Functions of Committee:-

- 1) The committee develops and updates comprehensive anti-ragging policies and guidelines that define what constitutes ragging, the penalties for engaging in it, and the reporting mechanisms. These policies are communicated to all students and staff members.
- 2) The committee conducts orientation programs for newly admitted students to educate them about the college's policies on ragging, its consequences, and the support mechanisms available to them.
- 3) The committee keeps a vigilant eye on the campus to detect any potential ragging activities. This involves regular inspections and interactions with students to ensure a safe atmosphere.
- 4) The committee establishes a system for students, faculty, and staff to report any incidents or suspicions of ragging. It thoroughly investigates these reports while maintaining the confidentiality of the complainants.

Anti-Ragging Rules and regulations:

- 1) Ragging is prohibited as per Act-26 of A.P. Legislative Assembly. 1997.
- 2) Ragging entails heavy fines or imprisonment.
- 3) All the student must carry their identity cards & show them when demanded.
- 4) Outsider are prohibited from entering the college without permission.

Sexual Harassment rules:

- 1) Provide a safe working environment at the college/workplace.
- 2) Treat sexual harassment as misconduct under the service rules & initiate action.
- 3) Forming an Internal Complaint Committee (ICC) at college.
- 4) ICC must observe the implementation of Anti-Sexual Harassment at College & recommend disciplinary actions if any to the employer's students



P. K. K. K.
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



घान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax: 011-2323 8858

E-mail: secy.ugc@nic.in

D. O. No. F. 3-2/2021 (ARC)

27 OCT 2021 October, 2021

'SPEED POST'

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, in pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" and in compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, **www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**.

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (**www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the regulations on curbing the menace of ragging. He/She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (Step 1 is the same like before).

Step 2: The student will receive an E MAIL with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the E mail of the Nodal officer in his/her university/college. **(Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case earlier).**

Step 3: The Nodal Officer in the university/college can click on the link of any forwarded e mails that he/she will receive from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

Contd.../-




UGC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Post, Tal. Warwa, Dist. Sangli

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.
(Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)
New Delhi-110002, the 17th June 2009

F.1-16/2007(CPP-II)

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SUP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student-or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause-(g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment .or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it



under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary-course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.



4. Definitions.-

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires, -
- a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
 - c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.
 - d) "Commission" means the University Grants Commission;
 - e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
 - f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
 - g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
 - h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
 - i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.



j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act; .

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

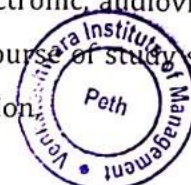
a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus, or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any Institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution.



and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any



other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,



parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.

m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.

n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.

o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available



when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

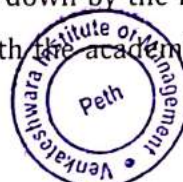
6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities?

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted o the institution in earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden *or* to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.



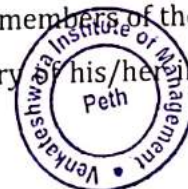
e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.



- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
- k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the Institution.
- l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
- m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year,
- n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.
- o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
- p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.



q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members; representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender,

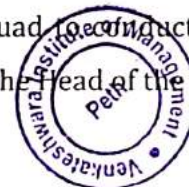
b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution.



or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person; as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1,

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry .. observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, In order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.



6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the dose vicinity thereof.
- b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among ail students residing in the hostel.
- c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
- d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
- e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
- f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
- g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards



and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice,

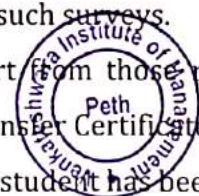
i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record,

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been



punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution,

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor or each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;



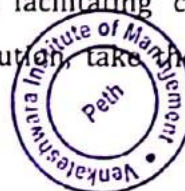
- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils. -

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;



a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.

b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.

c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;



- a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.
- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.
- f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency



responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging,-

9.1 The institution shall punish student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

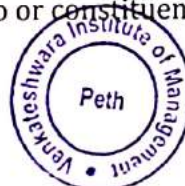
b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

- i. Suspension from attending classes and academic privileges.
- ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
- iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process,
- iv. Withholding results.
- v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- vi. Suspension/ expulsion from the hostel,
- vii. Cancellation of admission.
- viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters,
- ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

- i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;



- ii. in case of an order of a University, to its Chancellor.
- iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

- i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.
- ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies,

- iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any
- iv. Withholding any grants channelised through the university to the institution,
- v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary



action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps " to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one or more of the following measures, namely;

- i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
- ii. Withholding any grant allocated,
- iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
- iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
- v. Taking such other action within its-powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary



ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (Full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having been admitted to _____ (name of the institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the regulations and am aware as to what constitutes ragging

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that
a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

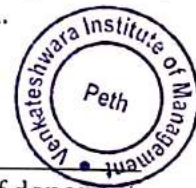
6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
Declared this ___ day of _____ month of ___ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).



Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, _____ full name of student with admission/registration/enrolment number _____, having been admitted to _____ (name of the institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the regulations and am aware as to what constitutes ragging

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of _____ month of ___ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

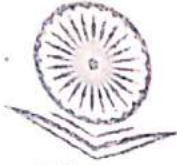
Verified at ___ (place) ___ on this the ___ (day) of ___ (month) ___, ___ (year) ___.



Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ___ (day) of ___ (month) ___, (year) ___ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



मानव-संसाधन विकास

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236208/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No. 14-4/2012(CPP-II)

7th December, 2018

PUBLIC NOTICE

ON

UGC (GRIEVANCE REDRESSAL) REGULATIONS, 2018

UGC had notified UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012 in official Gazette of India on **23rd March, 2013**. These regulations were aimed at addressing and effectively resolving grievances of students related to Higher Educational Institutions.

The UGC had received a number of responses on these regulations and hence constituted an Expert Committee to revisit UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012. The draft University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018 prepared by the Committee is attached herewith for observations and suggestions of stakeholders. The feedback and comments on the above draft may be sent to UGC via email grmhei.2018@gmail.com on or before **31st December, 2018**.

(Prof. Rajnish Jain)



P. K. Kulkarni
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002**

NOTIFICATION

F.No.14-4/2012 (CPP-II)

New Delhi, the __ October, 2018

In exercise of the power conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018.
- b) They shall apply to all HEIs, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations, and includes a person seeking admission to any institution of higher education;
- (c) "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any



qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

(d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.

(e) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub-regulation (1) of regulation 3;

(f) "grievances" include the following complaints of the aggrieved students, namely:

- i. making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
- ii. irregularity in the admission process adopted by the institution;
- iii. refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institution;
- iv. non publication of prospectus, (either hard copy / online) as specified in these regulations;
- v. publishing any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
- vi. withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a students for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
- vii. demand of money in excess of that specified in the declared admission policy to be charged by such institution;



- viii. breach in reservation policy in admission as may be applicable;
 - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority;
 - x. delay in conduct of examinations or declaration of results beyond the specified schedule in the academic calendar;
 - xi. on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
 - xii. non transparent or unfair evaluation practices;
 - xiii. Refund of fees, in case a student withdraws the admission within the stipulated time as mentioned in the prospectus, as notified by the Commission from time to time.
- (g) "Department Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department.
- (h) "Institutional Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of an Institution.
- (i) "College Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a college.
- (j) "University Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a University.
- (k) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1956;
- (l) "Institution" for the purposes of these regulations, means any university, college or such other institutions, as the case may be;
- (m) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached;



(n) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;

(o) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.

3. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

i. Every higher educational institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:

(a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;

(b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

(c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;

(d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;



- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules / regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular / visiting ---- and teaching experience of every member of its teaching faculty.
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution.
- (k) any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish / upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

- ii. Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its



publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (GRC):

A. Department Grievance Redressal Committee (DGRC)

- (i) In case of universities, all complaints relating to a department shall first be addressed to Department Grievance Redressal Committee (DGRC) to be constituted at the level of departments/school/center whose composition shall be as follows:
 - a) Head of the Department / School / Center – Chairperson
 - b) a Professor from outside the department / school / center to be nominated by the Head of HEI – Member
 - c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the Department – Member.
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.
- (v) The DGRC shall make efforts to resolve the grievance within the stipulated period and shall submit its report to the Head of the Institution within a period of 15 days from the date of receipt of complaint to the DGRC.
- (vi) The DGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

B. Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC)



- (i) The complaints not related to departments/schools / center and the grievances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC) to be constituted by Head of the HEI, whose composition shall be as follows:
 - (a) Pro-Vice Chancellor / Dean/ Senior academician of HEI – Chairperson.
 - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare
 - (c) Two senior academicians other than Chairperson.
 - (d) Proctor / Senior academician
- (ii) The above Committee shall be approved by the statutory body of institution (Executive Council or its equivalent).
- (iii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Committee members shall be two years.
- (iv) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.
- (v) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while giving its recommendations. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.
- (vi) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.
- (vii) The IGRC shall send the report and the recommendations to the Head of the HEI within in a period of 15 workings days from the date of receipt of grievance, or appeal or recommendations of the DGRC.
- (viii) The IGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

C. College Grievance Redressal Committee (CGRC)



- (i) In case of colleges, all complaints shall first be addressed to College Grievance Redressal Committee (CGRC) whose composition shall be as follows:
 - a) Principal of the college -Chairperson
 - b) Two senior faculty members nominated by the principal of the College.
- (ii) The tenure of the members shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and recommendations to the Vice-Chancellor of the affiliating university within a period of 15 days of receiving the complaint.

D. University Grievance Redressal Committee (UGRC)

- (i) In case of grievances not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Committee (UGRC) for which the Vice-chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Committee (UGRC) consisting of five members for a individual colleges or a group of colleges keeping in view the location of the college(s). The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the affiliating university consisting of :
 - a) A senior Professor of the university – Chairperson
 - b) Dean, Student Welfare or its equivalent - Member
 - c) Three Principals drawn from the affiliating colleges, on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor – Members
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.



(iv) The CGRC shall follow the principle of normal justice while deciding the grievance of the students.

(v) The CGRC shall send the report and the recommendations to the principal of the college within a period of 15 days of receiving the complaint.

E. Any person aggrieved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Committee or University Grievance Redressal Committee may within in a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

5. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each HEI shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students under these regulations.

(ii) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a retired Vice-Chancellor, Registrar or a faculty member who has at least ten years of experience as a Professor.

(iii) The Ombudsperson shall not be in any conflict of interest with the university, either before or after his appointment.

(iv) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not -

(a) hold or have held at any point in the past, any post or, employment in any office of profit in the university;

(b) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;

(c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.

(v) The Ombudsperson in a State University shall be appointed by the Executive council of the university on part-time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-



- (a) Nominee of the Governor of the State or his nominee - Chairperson
 - (b) Vice-Chancellor of a University of State to be nominated by the State Government – Member
 - (c) Vice-Chancellor of the concerned State University – Member
 - (d) Registrar of the concerned State University – Secretary (non-voting)
- (vi) The Ombudsperson in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Executive Council of the Central University or the equivalent statutory body of the Deemed to be University, as the case may be, on part - time basis from a panel of three member recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of University Grants Commission -- Chairperson,
- (b) One Vice Chancellor from Central University to be nominated by UGC (for Central Universities) – Member

OR

One Vice Chancellor from institution deemed to be university to be nominated by the UGC (for Deemed to be Universities) - Member

- (c) The Vice Chancellor of the university – Member
 - (d) The Registrar of the university – Secretary (Non-Voting)
- (vii) The Ombudsperson shall be a part time officer appointed for a period of three years from the date he/she assumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
- (viii) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as per the norms of the university for hearing the cases, in addition to the reimbursement of the conveyance.



- (ix) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under these regulations, by the concerned appointing authority i.e. the Executive Council of the University.

6. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear any appeal of an applicant for admission as student or student of the university against the university or institution affiliated to it as the case may be, after the student has availed all remedies available in such institution for redressal of grievance such as IGRC / UGRC;
- (ii) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, the issues of malpractices in the examination and evaluation processes may be referred to the Ombudsperson.
- (iii) Ombudsperson may seek the assistance of any person as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the student(s).

7. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSON AND GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that institution may submit an application seeking grievance redressal.
- (ii) On receipt of any online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Committee, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.
- (iii) The Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved person.



- (iv) An aggrieved person may appear either in person or be represented by such person as may be authorized to present his/her case.
- (v) The Grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Committee(s) shall be referred to the Ombudsperson.
- (vi) The institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Vice Chancellor.
- (vii) On the conclusion of proceedings, the Ombudsperson shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.
- (viii) Every order under the signature of the Ombudsperson shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. Any recommendations of the Ombudsperson not complied with by the institution shall be reported by the Ombudsperson to the Commission.
- (x) In case of any false or frivolous complaint, the Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant.

8. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSON GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

The institution shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee(s) and Ombudsperson on their website and in their prospectus prominently.

9. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal



Committee(s), as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) The Commission may take necessary and appropriate action as it may deemed fit, in case of an institution deemed to be university;
- (g) recommend to the concerned State Government for necessary and appropriate action, in case of a university established or incorporated under a State Act;
- (h) The Commission may take necessary and appropriate actions against any institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

(Prof. Rajnish Jain)
Secretary





DTE CODE - MB6224

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Anti-Ragging Committee

Academic Year 2021-22

Notice

I am pleased to inform you that the Anti-Ragging Committee is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 29 June, 2016 Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016 Members of the committee 2021-22 are as follows.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. S.B. Wadkar	Chairman
2	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
3	Miss. S. V. Tibe	Faculty Member
4	Adv. D. D. Patil	Advocate
5	Miss. P. J. Kadam	Student representative
6	Miss. D. B. Jadhav	Student representative


VC DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.





SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Anti-Ragging Committee

Academic Year 2020-21

Notice

I am pleased to inform you that the Anti-Ragging Committee is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 29 June, 2016 Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016 Members of the committee 2020-21 are as follows.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P. K. Katti	Chairman
2	Dr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S. V. Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D. Patil	Advocate
6	Mr. S.H. Mane	Student representative




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Anti-Ragging Committee

Academic Year 2019-20

Notice

I am pleased to inform you that the Anti-Ragging Committee is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 29 June, 2016 Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016 Members of the committee 2019-20 are as follows.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P. K. Katti	Chairman
2	Dr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S. V. Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D. Patil	Advocate
6	Mr. S.H. Mane	Student representative




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

OPE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Anti-Ragging Committee

Academic Year 2018-19

Notice

I am pleased to inform you that the Anti-Ragging Committee is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 29 June, 2016 Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016 Members of the committee 2018-19 are as follows.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P. K. Katti	Chairman
2	Dr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S. V. Tibe	Faculty Member
5	Adv. D. D. Patil	Advocate
6	Miss. D.V. Kamble	Student representative




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Anti-Ragging Committee

Academic Year 2017-18

Notice

I am pleased to inform you that the Anti-Ragging Committee is formed under the Maharashtra Public University Act, 2016 and the UGC Notification in Gazette of India on 29 June, 2016 Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016 Members of the committee 2017-18 are as follows.

Sr. No	Members	Designation
1	Dr. P. K. Katti	Chairman
2	Dr. S.B. Wadkar	Faculty Member
3	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member
4	Miss. S. V. Tibe	Faculty Member
5	Adv. S. Y. Sawant	Advocate
6	Miss. T.S.Patil	Student representative



Sy
VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

DVV Suggestion:-

3. Please provide Circular/web-link/ committee report justifying the objective of the metric.

HEI Reply:-

- Circular/web-link/ committee report justifying the objective of the metric is provided.




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 16/03/2022 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 11/03/2022



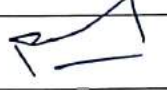

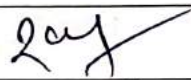
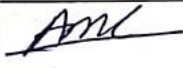



I/C Director
Venkateshwara Institute of Management,
Peth, Tal. Velha, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2021-22)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 16/03/2022 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. S. B. Wadkar	Member Secretary	
03	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
04	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
05	Mr. A. S. Patil	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

As the committee or the office of MBA had not received any complaint written or even orally by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.

Place: - Peth

Date :- 16/03/2022




I/C Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 20/09/2021 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 17/09/2021





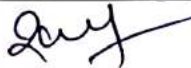
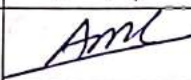



I/DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2020-21)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 20/09/2021 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. S. B. Wadkar	Member Secretary	
03	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
04	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
05	Mr. A. S. Patil	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

Member Secretary informed that due to the Covid-19 Pandemic situation first semester's meeting of CGRC was cancelled. And till today also there is no any written complaint received, as a result, the meeting concluded with vote of thanks.

Place: - Peth

Date: - 20/09/2021




Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 23/09/2019 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 20/09/2019




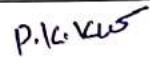





DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2019-20)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 23/09/2019 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Dr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

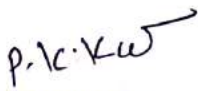
Resolution:-

As the issue of minor complains are redressed by concerned departments and committees effectively, no written complaint received to the committee. As a result, the meeting concluded with vote of thanks.

Place: - Peth

Date: - 23/09/2019




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 20/09/2018 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 17/09/2018

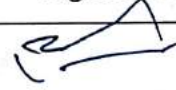
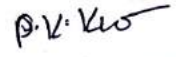


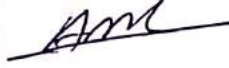



P. K. Kar
DIRECTOR
Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2018-19)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 20/09/2018 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Mr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

As the committee or the office of MBA had not received any complaint written or even orally by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.

Place: - Peth

Date: - 20/09/2018




DIRECTOR
Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 12/10/2017 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 09/10/2017


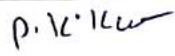

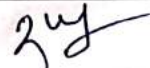
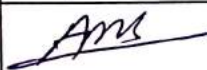



P.K. Kar
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2017-18)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 12/10/2017 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Mr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

As the issue of minor complains are redressed by concerned committees effectively had not received any written complaint by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.




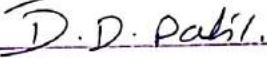

Place: - Peth

Date: - 12/10/2017




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

The meeting of the Anti-ragging Committee was held on 21/03/2022 at 4.30 P.M. in the Directors room. The following members were present.

Name of Committee member	Sign
1] Dr. S.B. Wadkar	
2] Asst. Prof. R.L. Chitnis	
3] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
4] Adv. D.D. Patil	
5] Miss. P.J. Kadam	

The following issues were discussed & the resolution were passed.

1] The proceeding of the last meeting held on 12/10/2021 was read by Mr. R.L. Chitnis & it was confirmed by all.

2] The main provision in the ragging act were discussed by the members Adv. D.D. Patil explained the provision & punishment under the act, & it was decided to take the action as per the act.

3] It was decided that to fill the online Anti-ragging form from students & submit its hard copy to college.

4) There was no any issue other than above, hence the meeting was finished.


DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2021-22

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. S. B. Wadkar, Faculty Members Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Miss. P.J. Kadam, Miss. D.B Jadhav student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2021-22 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 15 February 2022. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2021-22

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Managemen.
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

NOTICE NO-13




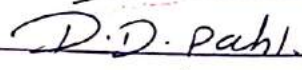
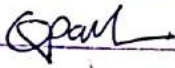
The meeting of the following members of the Anti-ragging Committee will be held on 12/10/2021 in the Director room at 4.30 P.M. All members are requested to remain present to discuss following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 11/10/2020
- 2] To make aware the student of MBA I & II in respect of Anti-ragging activities.
- 3] To discuss any other issues with the permission of chairman

Place - Peth

Date -




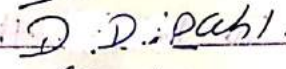
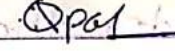
Name of Committee members	sign
---------------------------	------

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1] Dr. S. B. Wadkar |  |
| 2] Asst. Prof. R. L. Chitnis |  |
| 3] Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe |  |
| 4] Adv. D. D. Patil |  |
| 5] Miss. D. B. Jadhav |  |


DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

The meeting of the anti-ragging committee was held on 12/10/2021 at 4:30 pm. in the Directors room. The following members were present.

Name of members Sign

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1] Dr. S.B. Wadkar |  |
| 2] Asst. Prof R.L. Chitnis |  |
| 3] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe |  |
| 4] Adv. D.D. Patil |  |
| 5] Miss D.B. Jadhav |  |

The following issues were discussed & the resolution were passed.

- 1] The proceeding of the last meeting held on 11/10/2020 was accepted by the members who were present in the meeting.
- 2] The MBA I & II students should be made aware about the provision of Anti-ragging activities in educational Institution. The provision & Punishment under the ragging act were read by Prof. Miss. S.V. Tibe & Adv. D.D. Patil explained the provision & punishment under the act & it was decided to take action as per act.
- 3] There was no any issues other than above hence meeting was closed.


DIRECTOR

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2020-21

Venkateshwara Institute of Management appointed a Ragging committee to prevent the menace of ragging and maintain interpersonal relations among students in the college campus. Ragging is forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Mr. S. H Mane student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2020-21 all the college students are informed Anti ragging through prospectus all students filled their anti-ragging affidavit form and submitted to the class in charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.




IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwaz, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2020-21

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Path, Tal. Wahwa, Dist. Sangli.

The meeting of the Anti-ragging Committee was held on 11/10/2020 at 4.30 pm in the Directors room. The following member were present

Name of Committee members	sign
1. Dr. P. K. Katti	pkk
2. Dr. S. B. Wadkar	Sad
3. Asst. Prof. Mr. R. L. Chitnis	R L C
4. Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe	S V Tibe
5. Adv. D. D. Patil	D D Patil
6. Mr. S. H. Mane	S H Mane

The following issues were discussed & the resolution were passed.

- 1] The proceeding of the last meeting held on 09/10/2018 was read by Mr. R. L. Chitnis & it was confirmed by all
- 2] The main provisions in the ragging act were discussed by the members. Adv. D. D. Patil explained the provisions & punishment under the act, & it was decided to take the action as per the act.
- 3] It was decided that to fill the online Anti-ragging form from students & submit its hard copy to college

4] There was no any issue other than the above, hence the meeting was finished.


- DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2019-20

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Mr. S. H Mane student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2019-20 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 18 Sep 2018. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus




IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Sangli, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2019-20

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Manageme.
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

MEETING NO. 11

The meeting of the anti-ragging committee was held on 09/10/18 at 4:30 pm in the Directors room. The following members were present

Name of members	Sign
1. Dr. P.K. Katti	
2. Dr. S.B. Wadkar	
3. Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4. Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5. Adv. D.D. Patil	
6. Miss. D.V. Kamble	

The following issues were discussed & the resolutions were passed.

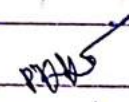
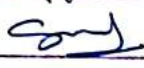
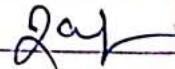


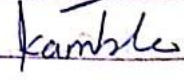
- 1] The proceedings of the last meeting held on 04/10/17 was accepted by the members who were present in the meeting.
- 2] The MBA I & II students should be made aware about the provisions of Anti-ragging activities in educational institutions. The provision & Punishment under the ragging act were read by Prof. Miss S.V. Tibe & Adv. D.D. Patil explained the provision & Punishment under the act & it was decided to take the action as per act.
- 3] There was no any issues other than the above hence meeting was closed.

NOTICE NO. 11

The meeting of the following member of the Anti-ragging Committee will be held on 09/10/2018 in the directors room at 4.30 PM. All members are requested to remain present to discuss following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 04/10/2017
- 2] To make aware the students of MBA I & II in respect of Anti-ragging activities.
- 3] To discuss any other issues with the permission of chairman.

Place - Peth
Date - 07/10/2018

Name of Committee members	Sign
1] Dr. P.K. Katti	
2] Dr. S.B. Wadkar	
3] Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5] Adv. D.D. Patil	
6] Miss. D.V. Kamble	


DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli/Rajshree

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2018-19

Venkateshwara Institute of Management appointed a Ragging committee to prevent the menace of ragging and maintain interpersonal relations among students in the college campus. Ragging is forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Miss. D. V Kamble student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2018-19 all the college students are informed Anti ragging through prospectus all students filled their anti-ragging affidavit form and submitted to the class in charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2018-19

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0



P.K.K.
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

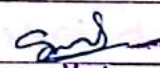


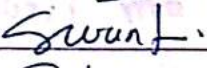
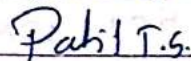
Notice No-10

The meeting of the following members of the Anti-ragging committee will be held on 05/10/2018 in the directors room at 4.30 pm. All members are requested to remain present to discuss the following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 03/10/2016
- 2] To know the provisions of the Anti-ragging under the anti-ragging Act-1999.
- 3] To suggest the procedure & methods to control the ragging among
- 4] To take note of the complaints, issues received by the students if any.
- 5] To discuss any other issues related to ragging with the permission of chairman.

Place: Peth

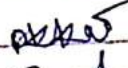
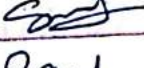
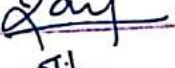

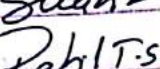
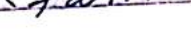
Date: 03/10/2018

1. Dr. P. K. Katti
2. Asst Prof. S. B. Wadkar  **DIRECTOR**
3. Asst Prof. R. L. Chitnis  Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.
4. Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe 
5. Adv. S. Y. Swant 
6. Miss. T. S. Pahl 

Meeting No 10.

The meeting of anti-ragging committee was held on 04/10/2018 at 4.30 PM in the directors room.

The following members were present.

Name	Sign
1. Dr. P.K. Katti	
2. Asst. Prof. S.B. Wadkar	
3. Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4. Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5. Adv. S.V. Sawant	
6. Miss. T.S. Patil	

The following issues were discussed & the resolutions were passed.

1] The proceeding of the last meeting held on 23/10/2016 was read by Mr. R.L. Chitnis and it was confirmed by all.

2] The MBA Post-IAT students should be made aware about the provisions of the anti-ragging activities in educational institutions. The provision & punishment under the ragging act were read by Prof. Adv. S.V. Sawant and it was decided to hold the questions answer session for the students.

3] There were no other issues than the above hence the meeting was closed.


DIRECTOR

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2017-18

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Mr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. S.Y Sawant, Miss T. S Patil student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2017-18 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 15 Sep 2017. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2017-18

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0



P. K. Kulkarni
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.


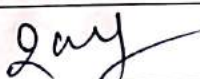



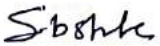

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2021-22)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 15-03-2022 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 24/12/2021
- 2) To discuss about arranging guest lecture on Definition, Scope & remedies regarding sexual harassment for MBA I & II students to create awareness among them.
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Mr. A. S. Patil	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. J. Kadam	






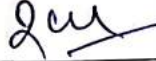
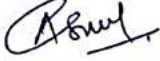

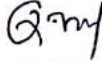
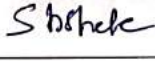

I/C DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tel. Wadga, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2021-22) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 15-03-2022 in director cabin following members attended the meeting

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Mr. A. S. Patil	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. J. Kadam	

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. R.L Chitnis & it was confirmed by all.

Resolution No.2

In meeting committee members decided to arrange guest lecture on definition, Scope & remedies of sexual harassment for MBA I & II year Students & for that they decide to Invite advocate D.D Patil.

Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.3

There was no issue other than above hence the meeting was closed




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.


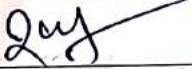


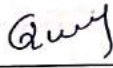
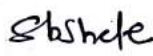
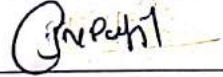
Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2020-21)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are hereby informed that there will be meeting on 24-12-2021 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 23/09/2019
- 2) Matter arising out of previous meeting
- 3) To introduce proactive measures to prevent sexual harassment if occurring.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Dr. A.M Kharat	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. J.V Patil	



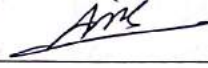

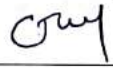
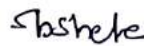
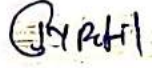



I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2020-21) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 24-12-2021 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Dr. A.M Kharat	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. J.V Patil	

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Dr. A.M Kharat & it was confirmed by all.

Resolution No.2

The meeting participants unanimously resolve that there are no matters arising from the previous meeting.


Resolution No.3

Recognizing the importance of fostering a safe and respectful college environment where all students can thrive academically, personally, and professionally.

Resolution No.3

There was no issue other than above hence the meeting was closed




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwra, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2019-20)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 23-09-2019 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 14/09/2018
- 2) To Discuss on improvement of facilities of ladies room
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	<i>P.K.Katti</i>
2	Dr. S.B. Wadkar	<i>S.B.Wadkar</i>
3	Mr. R. L. Chitnis	<i>R.L.Chitnis</i>
4	Miss. S.V Tibe	<i>S.V.Tibe</i>
5	Adv. D. D Patil	<i>D.D.Patil</i>
6	Dr. S.B Shete	<i>S.B.Shete</i>
7	Miss. V.S Deshmukh Patil	<i>V.S.Deshmukh Patil</i>

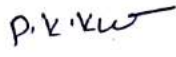

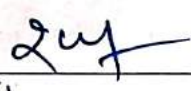


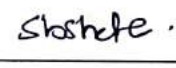



P.K.Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walva Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2019-20) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 23-09-2019 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	
2	Dr. S.B. Wadkar	
3	Mr. R. L. Chitnis	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. V.S Deshmukh Patil	

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. R.L Chitnis & it was confirmed by all.

Resolution No.2

Facilitate a discussion to identify specific areas that require improvement within the ladies' room. Consider aspects such as cleanliness, accessibility, privacy, lighting, ventilation, and amenities.

Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

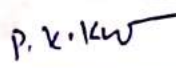

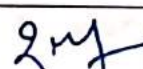


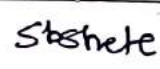

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2018-19)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 14-09-2018 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 20/09/2017
- 2) Discussion on legal awareness about sexual harassment by the guidelines of Adv. D. D. Patil.
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	
2	Mr. S.B. Wadkar	
3	Mr. R. L. Chitnis	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. D.V. Kamble	




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2018-19) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 14-09-2018 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	P.K.Katti
2	Mr. S.B. Wadkar	S.B. Wadkar
3	Mr. R. L. Chitnis	R.L. Chitnis
4	Miss. S.V Tibe	S.V. Tibe
5	Adv. D. D Patil	D.D. Patil
6	Dr. S.B Shete	S.B. Shete
7	Miss. D.V. Kamble	D.V. Kamble

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No-1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. S.B. Wadkar & it was confirmed by all.

Resolution No.2

On the occasion of this programme Adv. D.D.Patil sir gives information regarding various acts and punishments on sexual harassment and how to protect themselves from bad habitat to our college girls.

Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

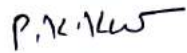



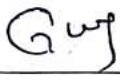
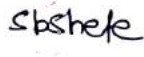

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2017-18)

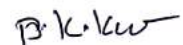
NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 20-09-2017 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 09/09/2016
- 2) Discussion on changing place of complaint box.
- 3) To check complaints from complaint box.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	
2	Mr. S.B. Wadkar	
3	Mr. R. L. Chitnis	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. A. Kadam	




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2017-18) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 20-09-2017 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	<i>P.K.Katti</i>
2	Mr. S.B. Wadkar	<i>S.B. Wadkar</i>
3	Mr. R. L. Chitnis	<i>R.L. Chitnis</i>
4	Miss. S.V Tibe	<i>S.V. Tibe</i>
5	Adv. D. D Patil	<i>D.D. Patil</i>
6	Dr. S.B Shete	<i>S.B. Shete</i>
7	Miss. P. A. Kadam	<i>P.A. Kadam</i>

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. S.B. Wadkar & it was confirmed by all.

Resolution No.2

Students face difficulty to find the complaint box so college decided to shift the complaint box to the outside the office.

Resolution No.3

Committee must handle the complaints discreetly and take appropriate measures to protect the identities of the individuals involved.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed



P.K.Katti
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

DVV Suggestion:-

4. Please provide minutes of the meetings of student grievance committee, as per metric.

HEI Reply:-

- Minutes of the meetings of student grievance committee, as per metric are provided.**




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth Naka, Walwa, Sangli, (MH) 415 407

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 16/03/2022 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 11/03/2022



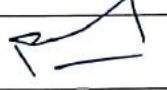

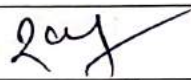
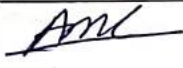



I/C Director
Venkateshwara Institute of Management,
Peth, Tal. Velha, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2021-22)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 16/03/2022 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. S. B. Wadkar	Member Secretary	
03	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
04	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
05	Mr. A. S. Patil	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

As the committee or the office of MBA had not received any complaint written or even orally by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.

Place: - Peth

Date :- 16/03/2022




I/C Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 20/09/2021 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 17/09/2021





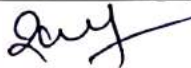
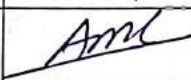



I/DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2020-21)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 20/09/2021 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. S. B. Wadkar	Member Secretary	
03	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
04	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
05	Mr. A. S. Patil	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

Member Secretary informed that due to the Covid-19 Pandemic situation first semester's meeting of CGRC was cancelled. And till today also there is no any written complaint received, as a result, the meeting concluded with vote of thanks.

Place: - Peth

Date: - 20/09/2021




Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 23/09/2019 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 20/09/2019




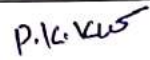





DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2019-20)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 23/09/2019 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Dr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

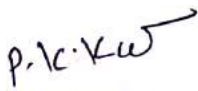
Resolution:-

As the issue of minor complains are redressed by concerned departments and committees effectively, no written complaint received to the committee. As a result, the meeting concluded with vote of thanks.

Place: - Peth

Date: - 23/09/2019




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 20/09/2018 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 17/09/2018

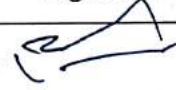
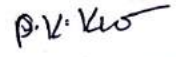


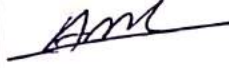



P. K. Kar
DIRECTOR
Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2018-19)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 20/09/2018 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Mr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

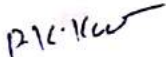
Resolution:-

As the committee or the office of MBA had not received any complaint written or even orally by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.

Place: - Peth

Date: - 20/09/2018




DIRECTOR
Director
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

NOTICE

The meeting of the Grievance Redressal Committee will be held in the office of the Secretary of MBA College on 12/10/2017 to discuss about the complaints & suggestions regarding the redressal committee. All the members are requested to remain present for the meeting.

Place: Peth

Date: - 09/10/2017


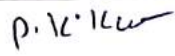

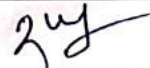
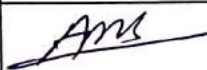



P.K. Kar
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Minutes of the College Grievance Redressal Committee (2017-18)

The meeting of Grievance Redressal Committee was held on 12/10/2017 in the Secretary office. The following members were present for the meeting.

Sr. No.	Name	Designation	Signature
01	Mr. R. N. Mahadik	Chairman	
02	Dr. P. K. Katti	Member Secretary	
03	Mr. S. B. Wadkar	Faculty Member	
04	Mr. R. L. Chitnis	Faculty Member	
05	Dr. A. M. Kharat	Faculty Member	
06	Mr. S. R. Jadhav	Non-Teaching Member	

Resolution:-

As the issue of minor complains are redressed by concerned committees effectively had not received any written complaint by any teaching & non-teaching members of the college. Hence, the meeting was ended.

Place: - Peth

Date: - 12/10/2017




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.


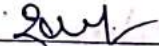

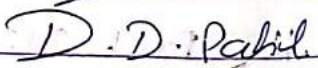

NOTICE NO: 14


The meeting of the following members of the Anti-ragging committee will be held on 21/03/22 in the Directors room at 4.30 P.M. All the members are requested to remain present to discuss the following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 12/10/2021
- 2] To know the provision of the Anti-ragging under the ragging act 1999.
- 3] To suggest the procedure & method to control the ragging among the students.
- 4] To discuss any other issue related to ragging.




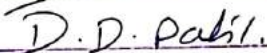

Name of Committee members

Sign

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1] Dr. S.B. Wadkar |  |
| 2] Asst. Prof. R.L. Chitnis |  |
| 3] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe |  |
| 4] Adv. D.D. Patil |  |
| 5] Miss. P.J. Kadam |  |


DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

The meeting of the Anti-ragging Committee was held on 21/03/2022 at 4.30 P.M. in the Directors room. The following members were present.

Name of Committee member	Sign
1] Dr. S.B. Wadkar	
2] Asst. Prof. R.L. Chitnis	
3] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
4] Adv. D.D. Patil	
5] Miss. P.J. Kadam	

The following issues were discussed & the resolution were passed.

1] The proceeding of the last meeting held on 12/10/2021 was read by Mr. R.L. Chitnis & it was confirmed by all.

2] The main provision in the ragging act were discussed by the members Adv. D.D. Patil explained the provision & punishment under the act, & it was decided to take the action as per the act.

3] It was decided that to fill the online Anti-ragging form from students & submit its hard copy to college.

4) There was no any issue other than above, hence the meeting was finished.


*DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2021-22

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. S. B. Wadkar, Faculty Members Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Miss. P.J. Kadam, Miss. D.B Jadhav student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2021-22 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 15 February 2022. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2021-22

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Managemen.
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

NOTICE NO-13




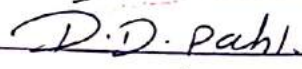
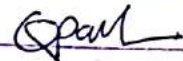
The meeting of the following members of the Anti-ragging Committee will be held on 12/10/2021 in the Director room at 4.30 P.M. All members are requested to remain present to discuss following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 11/10/2020
- 2] To make aware the student of MBA I & II in respect of Anti-ragging activities.
- 3] To discuss any other issues with the permission of chairman

Place - Peth

Date -




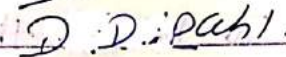
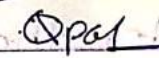
Name of Committee members	sign
---------------------------	------

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1] Dr. S. B. Wadkar |  |
| 2] Asst. Prof. R. L. Chitnis |  |
| 3] Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe |  |
| 4] Adv. D. D. Patil |  |
| 5] Miss. D. B. Jadhav |  |


DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

The meeting of the anti-ragging committee was held on 12/10/2021 at 4:30 pm. in the Directors room. The following members were present.

Name of members Sign

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1] Dr. S.B. Wadkar |  |
| 2] Asst. Prof R.L. Chitnis |  |
| 3] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe |  |
| 4] Adv. D.D. Patil |  |
| 5] Miss D.B. Jadhav |  |

The following issues were discussed & the resolution were passed.

- 1] The proceeding of the last meeting held on 11/10/2020 was accepted by the members who were present in the meeting.
- 2] The MBA I & II students should be made aware about the provision of Anti-ragging activities in educational Institution. The provision & Punishment under the ragging act were read by Prof. Miss. S.V. Tibe & Adv. D.D. Patil explained the provision & punishment under the act & it was decided to take action as per act.
- 3] There was no any issues other than above hence meeting was closed.


DIRECTOR

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2020-21

Venkateshwara Institute of Management appointed a Ragging committee to prevent the menace of ragging and maintain interpersonal relations among students in the college campus. Ragging is forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Mr. S. H Mane student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2020-21 all the college students are informed Anti ragging through prospectus all students filled their anti-ragging affidavit form and submitted to the class in charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.




IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwz, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2020-21

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Path, Tal. Wahwa, Dist. Sangli.

NOTICE NO-12

The meeting of the following members of the Anti-ragging Committee will be held on 11/10/2020 in the Directors room at 4.30 PM. All the members are requested to remain present to discuss the following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 09/10/2018
- 2] To know the provision of the Anti-ragging under the Ragging Act 1999
- 3] To suggest the procedure & method to control the ragging among the students.
- 4] To discuss any other issue related to ragging

Name of committee members

Sign

1] Dr. P.K. Katti

P.K.K

2] Dr. S.B. Wadkar

S.B.W

3] Asst. Prof. R.L. Chitnis

R.L.C

4] Asst. Prof. Miss S.V. Tibe

S.V.T

5] Adv. D.D. Patil

D.D.P

6] Mr. S.H. Mane

S.H.M

P.K.K
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

The meeting of the Anti-ragging Committee was held on 11/10/2020 at 4.30 pm in the Directors room. The following member were present

Name of Committee members	Sign
1. Dr. P. K. Katti	pkk
2. Dr. S. B. Wadkar	Sad
3. Asst. Prof. Mr. R. L. Chitnis	R. L. Chitnis
4. Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe	S. V. Tibe
5. Adv. D. D. Patil	D. D. Patil
6. Mr. S. H. Mane	S. H. Mane

The following issues were discussed & the resolution were passed.

- 1] The proceeding of the last meeting held on 09/10/2018 was read by Mr. R. L. Chitnis & it was confirmed by all
- 2] The main provisions in the ragging act were discussed by the members. Adv. D. D. Patil explained the provisions & punishment under the act, & it was decided to take the action as per the act.
- 3] It was decided that to fill the online Anti-ragging form from students & submit its hard copy to college

4] There was no any issue other than the above, hence the meeting was finished.


- DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2019-20

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Mr. S. H Mane student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2019-20 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 18 Sep 2018. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus




IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Sangli, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2019-20

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Manageme.
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

MEETING NO. 11

The meeting of the anti-ragging committee was held on 09/10/18 at 4:30 pm in the Directors room. The following members were present

Name of members	Sign
1. Dr. P.K. Katti	
2. Dr. S.B. Wadkar	
3. Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4. Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5. Adv. D.D. Patil	
6. Miss. D.V. Kamble	

The following issues were discussed & the resolutions were passed.

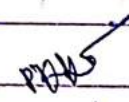
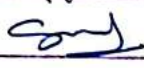
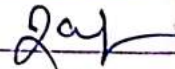


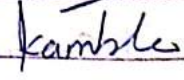
- 1] The proceedings of the last meeting held on 04/10/17 was accepted by the members who were present in the meeting.
- 2] The MBA I & II students should be made aware about the provisions of Anti-ragging activities in educational institutions. The provision & Punishment under the ragging act were read by Prof. Miss S.V. Tibe & Adv. D.D. Patil explained the provision & Punishment under the act & it was decided to take the action as per act.
- 3] There was no any issues other than the above hence meeting was closed.

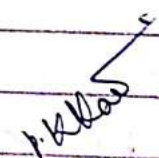
NOTICE NO. 11

The meeting of the following member of the Anti-ragging Committee will be held on 09/10/2018 in the directors room at 4.30 PM. All members are requested to remain present to discuss following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 04/10/2017
- 2] To make aware the students of MBA I & II in respect of Anti-ragging activities.
- 3] To discuss any other issues with the permission of chairman.

Place - Peth
Date - 07/10/2018

Name of Committee members	Sign
1] Dr. P.K. Katti	
2] Dr. S.B. Wadkar	
3] Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4] Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5] Adv. D.D. Patil	
6] Miss. D.V. Kamble	


DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli/Rajshree

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2018-19

Venkateshwara Institute of Management appointed a Ragging committee to prevent the menace of ragging and maintain interpersonal relations among students in the college campus. Ragging is forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Dr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. D.D Patil, Miss. D. V Kamble student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2018-19 all the college students are informed Anti ragging through prospectus all students filled their anti-ragging affidavit form and submitted to the class in charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus.



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2018-19

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0



P.K.K.
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

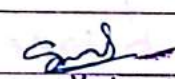


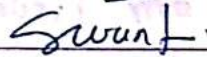
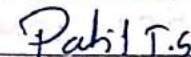
Notice No-10

The meeting of the following members of the Anti-ragging committee will be held on 05/10/2018 in the directors room at 4.30 pm. All members are requested to remain present to discuss the following items.

- 1] To confirm the last meeting proceeding held on 03/10/2016
- 2] To know the provisions of the Anti-ragging under the anti-ragging Act-1999.
- 3] To suggest the procedure & methods to control the ragging among
- 4] To take note of the complaints, issues received by the students if any.
- 5] To discuss any other issues related to ragging with the permission of chairman.

Place: Peth

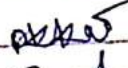
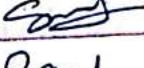
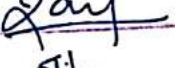

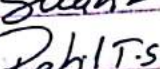
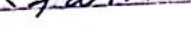
Date: 03/10/2018

1. Dr. P. K. Katti
2. Asst Prof. S. B. Wadkar  **DIRECTOR**
3. Asst Prof. R. L. Chitnis  Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.
4. Asst. Prof. Miss. S. V. Tibe  S. Tibe
5. Adv. S. Y. Swant.  Swant.
6. Miss. T. S. Pahl.  Pahl T. S.

Meeting No 10.

The meeting of anti-ragging committee was held on 04/10/2018 at 4.30 PM in the directors room.

The following members were present.

Name	Sign
1. Dr. P.K. Katti	
2. Asst. Prof. S.B. Wadkar	
3. Asst. Prof. R.L. Chitnis	
4. Asst. Prof. Miss. S.V. Tibe	
5. Adv. S.V. Sawant	
6. Miss. T.S. Patil	

The following issues were discussed & the resolutions were passed.

1] The proceeding of the last meeting held on 23/10/2016 was read by Mr. R.L. Chitnis and it was confirmed by all.

2] The MBA Post-IAT students should be made aware about the provisions of the anti-ragging activities in educational institutions. The provision & punishment under the ragging act were read by Prof. Adv. S.V. Sawant and it was decided to hold the questions answer session for the students.

3] There were no other issues than the above hence the meeting was closed.


DIRECTOR

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee
Report 2017-18

To prevent, the menace of ragging and maintain healthy interpersonal relations among students in the college campus of Venkateshwara Institute of Management, Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. For this Purpose the Anti-Ragging Committee has been actively functioning. The committee includes the honorable members Chairman Dr. P.K Katti Director of VIM Peth, Faculty Members Mr. S. B. Wadkar, Mr. R.L Chitnis, Miss S.V Tibe, Adv. S.Y Sawant, Miss T. S Patil student's representative. All are actively take efforts to maintain the clam and quite environment in college campus.

In the academic year 2017-18 all the college student especially fresher's were counseled by college director and give the information about anti-ragging on 15 Sep 2017. All students filled their anti-ragging affidavit from and submitted to the Class in Charge. In the year there were not happened any minor ragging case in the campus



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Cell

2017-18

Total Grievances received	Number of Grievances redressed	Average number of days Grievances redressed
0	0	0



P. K. Kulkarni
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.


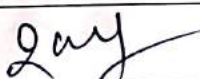



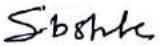

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2021-22)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 15-03-2022 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 24/12/2021
- 2) To discuss about arranging guest lecture on Definition, Scope & remedies regarding sexual harassment for MBA I & II students to create awareness among them.
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Mr. A. S. Patil	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. J. Kadam	






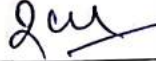
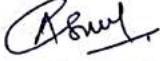

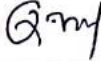
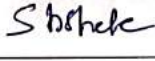
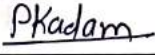
I/C DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tel. Waha, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2021-22) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 15-03-2022 in director cabin following members attended the meeting

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Mr. A. S. Patil	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. J. Kadam	

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. R.L Chitnis & it was confirmed by all.

Resolution No.2

In meeting committee members decided to arrange guest lecture on definition, Scope & remedies of sexual harassment for MBA I & II year Students & for that they decide to Invite advocate D.D Patil.


Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.3

There was no issue other than above hence the meeting was closed




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.


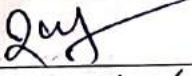


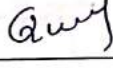
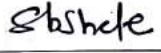
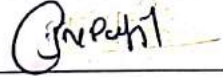
Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2020-21)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are hereby informed that there will be meeting on 24-12-2021 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 23/09/2019
- 2) Matter arising out of previous meeting
- 3) To introduce proactive measures to prevent sexual harassment if occurring.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Dr. A.M Kharat	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. J.V Patil	



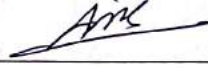

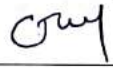
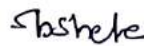
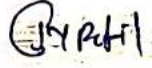



VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2020-21) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 24-12-2021 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. S.B. Wadkar	
2	Mr. R. L. Chitnis	
3	Dr. A.M Kharat	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. J.V Patil	

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Dr. A.M Kharat & it was confirmed by all.

Resolution No.2

The meeting participants unanimously resolve that there are no matters arising from the previous meeting.


Resolution No.3

Recognizing the importance of fostering a safe and respectful college environment where all students can thrive academically, personally, and professionally.

Resolution No.3

There was no issue other than above hence the meeting was closed




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwra, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2019-20)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 23-09-2019 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 14/09/2018
- 2) To Discuss on improvement of facilities of ladies room
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	<i>P.K.Katti</i>
2	Dr. S.B. Wadkar	<i>S.B.Wadkar</i>
3	Mr. R. L. Chitnis	<i>R.L.Chitnis</i>
4	Miss. S.V Tibe	<i>S.V.Tibe</i>
5	Adv. D. D Patil	<i>D.D.Patil</i>
6	Dr. S.B Shete	<i>S.B.Shete</i>
7	Miss. V.S Deshmukh Patil	<i>V.S.Deshmukh Patil</i>



P.K.Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2019-20) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 23-09-2019 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	P.K.Katti
2	Dr. S.B. Wadkar	S.B.Wadkar
3	Mr. R. L. Chitnis	R.L.Chitnis
4	Miss. S.V Tibe	S.V.Tibe
5	Adv. D. D Patil	D.D.Patil
6	Dr. S.B Shete	S.B.Shete
7	Miss. V.S Deshmukh Patil	V.S.Deshmukh Patil

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. R.L Chitnis & it was confirmed by all.

Resolution No.2

Facilitate a discussion to identify specific areas that require improvement within the ladies' room. Consider aspects such as cleanliness, accessibility, privacy, lighting, ventilation, and amenities.

Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed



P.K.Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

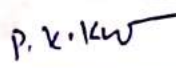

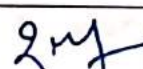


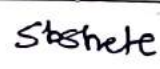

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2018-19)

NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 14-09-2018 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 20/09/2017
- 2) Discussion on legal awareness about sexual harassment by the guidelines of Adv. D. D. Patil.
- 3) To take Note of all complaints, issue received by the students in any.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	
2	Mr. S.B. Wadkar	
3	Mr. R. L. Chitnis	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. D.V. Kamble	




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2018-19) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 14-09-2018 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	P.K.Katti
2	Mr. S.B. Wadkar	S.B. Wadkar
3	Mr. R. L. Chitnis	R.L. Chitnis
4	Miss. S.V Tibe	S.V. Tibe
5	Adv. D. D Patil	D.D. Patil
6	Dr. S.B Shete	S.B. Shete
7	Miss. D.V. Kamble	D.V. Kamble

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No-1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. S.B. Wadkar & it was confirmed by all.

Resolution No.2

On the occasion of this programme Adv. D.D.Patil sir gives information regarding various acts and punishments on sexual harassment and how to protect themselves from bad habitat to our college girls.

Resolution No.3

There was no any note of Complaints issues received by students so it was not discussed.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed



P.K. Katti
DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

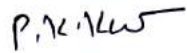



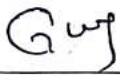
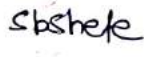

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2017-18)

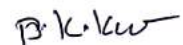
NOTICE

All the members of Internal Complaints Committee are here by informed that there will be meeting on 20-09-2017 to discuss on following subjects in the Director room at 4.30 PM. All the members are requested to attend .The meeting Agenda will be as follows.

- 1) To confirm the last meeting held on 09/09/2016
- 2) Discussion on changing place of complaint box.
- 3) To check complaints from complaint box.
- 4) To discuss any other issues with the permission of chairman.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	
2	Mr. S.B. Wadkar	
3	Mr. R. L. Chitnis	
4	Miss. S.V Tibe	
5	Adv. D. D Patil	
6	Dr. S.B Shete	
7	Miss. P. A. Kadam	




DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaint Committee (2017-18) - Minutes of Meeting

The meeting of Internal Complaints Committee was held on 20-09-2017 in director cabin following members attended the meeting.

Sr. No	Members	Sign
1	Dr. P.K. Katti	<i>P.K.Katti</i>
2	Mr. S.B. Wadkar	<i>S.B. Wadkar</i>
3	Mr. R. L. Chitnis	<i>R.L. Chitnis</i>
4	Miss. S.V Tibe	<i>S.V. Tibe</i>
5	Adv. D. D Patil	<i>D.D. Patil</i>
6	Dr. S.B Shete	<i>S.B. Shete</i>
7	Miss. P. A. Kadam	<i>P.A. Kadam</i>

The following issues were discussed & there solutions were passed.

Resolution No -1

The proceeding of the last meeting held on was read by Mr. S.B. Wadkar & it was confirmed by all.

Resolution No.2

Students face difficulty to find the complaint box so college decided to shift the complaint box to the outside the office.

Resolution No.3

Committee must handle the complaints discreetly and take appropriate measures to protect the identities of the individuals involved.

Resolution No.4

There was no issue other than above hence the meeting was closed



P.K.Katti
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

DTE CODE - MB6224

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

DVV Suggestion:-

5. Kindly note that the mechanism of redressal should be available as document and should be hosted in the HEI's Website. As the link of the same shall be provided to validate the same.

HEI Reply:-

- The document of mechanism of redressal is hosted on website. The link for document is
- <https://vim.org.in/grievance-redressal.php>

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

DVV Suggestion:-

6. Kindly provide Statutory regulations/norms of UGC/SRA.

HEI Reply:-

- Statutory regulations/norms of UGC/SRA are provided.



Sy
I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa Dist. Sangli.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है. नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में-बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

(अ) "पीडित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला-चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं सन्नाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैंटीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो-जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

2136 GI/2016





I/C DIRECTOR

Venkateshvara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु-अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है—यह समस्त उक्त परिचर में सम्मिलित हैं।

- (डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है;
- (ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत का दाखल करना—अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;
- (एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उक्त व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन-सहायक शोध-सहायक चाहे वे रोजगार में हैं अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परिशौजनाओं लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;
- (जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हैं— तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवाओं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;
- (एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचई.आई.) से अर्थ है—एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;
- (आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

बराती, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बराती कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;


- (जे) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कामूतों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है— जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न मामलों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमे में बतौर गवाह मौजूद रहना;

- (क) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है—

- (1) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अस्पष्ट मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और तमकी भय वातावरण पैदा करती हैं अथवा चरमक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर धरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः—

- (अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अत्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण
- (ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना
- (स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना




 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tal. Waiwa, Dist. Sangli.

- (ङ) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पारा बने रहने की कोशिश करना
- (झ) अश्लील साहित्य दिखाना
- (ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं—
- (अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में है;
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;
- (स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;
- (द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;
- (ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;
- (एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हः
- बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है— यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:
- बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;
- (एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है—बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;
- (ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:
- (अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवारशीय है या नहीं या उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।
3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व—(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)
- (अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना,
- (ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना;



SIL

VC DIRECTOR
Vankateshvara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

- (स) जैसा कि आयोग की "सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम) रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुगम बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित बनाना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;
- (द) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना;
- (ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;
- (एफ) सभी स्तरों पर अपने परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;
- (जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है— तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;
- (एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नॉटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी सनुदायों के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी लक्ष्य के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेन्डर सेन्सिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हारसमेंट—जी.एस.सी. ए.एस.एच. निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटी—आई.सी.सी.) के समान ही पुनर्गठित करना;
- गर्भार्थ, बाद में दर्शाये गए मामलों में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा:
- (आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;
- (जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- (के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से गतिशील बनाना चाहें वह उत्पीड़न किसी प्रयत्न अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो।
- (एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना अथवा विधि द्वारा मान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अपरोध हेतु तन्त्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;
- (एम) यदि उस दुराचार का षडयंत्रकारी वहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;
- (एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्मक नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;
- (ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;
- (पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;
- (क्व) एक जर्मिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, यह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ—

- (1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र (आई.सी.सी.) प्रकाशित करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय-समय पर संशोधित किया




 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tal. Wahwa, Dist. Sangli.

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुरार अधिनियम लागू किया जाना है,

- (2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकाशित के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आवंटन भी हो;
- (3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से सामर्थ्य से असुरक्षा तानाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है;
- (4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध संरक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं;
- (5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अग्रिमूखी एवं पुनरुत्थान पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;
- (7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;
- (8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए;
- (9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार ये स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है;
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए;
- (11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से ये स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शान के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए;
- (12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है;



I/C DIRECTOR

Venkateshvara Institute of Management
Path, Tal. Warwa, Dist. Sangli.

- (13) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभाव पूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना— विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए;
- (14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ होनी अविदेशात्मक हैं। महिलाओं के दिग्घ्न में इस प्रक्रिया में लिंग संबंधी डाक्टर और नर्स तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए;
- (15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ पुनः चालू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही ये आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियाँ विस्तारित करेंगी जिनमें लैंगिक संबंधीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगी। "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल" इन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि ये कार्यशालाएँ नवोन्मेषी, आकर्षक बनें एवं नशीली न हों;
- (16) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्य, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जवाबदेही के दायरे में यथाआवश्यक रूप से लाना चाहिए;

4. शिकायत समाधान तन्त्र—

- (1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदाकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी. की निम्न संरचना होगी—
- (अ) एक पीठासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर (एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह-प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- बशर्त यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को उप-अनुभाग 2(अ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगा;
- "बशर्त यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियुक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"
- (ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर-अध्यापन स्तर कर्मचारी जो अधिमान्त महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए;
- (स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातक स्तर एवं शोधस्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;
- (द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी संघ में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;
- (2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए;
- (3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, पदम कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसी केन्द्र के प्रकार्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे;



Sd/-
VC DIRECTOR
 Venkateshvara Institute of Management
 Peth, Tal. Wazwa, Dist. Sangli.

- (4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केंद्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;
- (5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है;
- (6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि—
- (अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
 - (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
 - (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा
 - (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी संवामें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;
- तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;"

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :- आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
- (ब) विवाद समाधान के हेतु वातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मंत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े,
- (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अयकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा,
- (द) तैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
- (इ) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्यवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

6. शिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:- आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह सन्तुष्ट रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे,

7. तैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :- किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हों तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें,

वर्शते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा,

वर्शते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर सन्तुष्ट सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:-



VC DIRECTOR
Venkateswara Institute of Management
Path, Tal. Wotera, Dist. Sangli.

- (1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी,
- (2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पत्तों के नामों एवं उनके पत्तों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा,
- (3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जाँच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि व हों, तो, जाँच पड़ताल रिपोर्ट उस जाँच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जाँच के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी,
- (4) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जाँच के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो,
- (5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों/अनुशंसाओं के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है,
- (6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है— उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही करेंगे,
- (7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होगा चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथार्थि उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलन कराएगा। किसी भी दण्डात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है,
- (8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जाँच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा,
9. आन्तरिक समाधान— उच्चतर शैक्षिक संस्थान,
- (अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्याय क्रिया में शामिल जाखिम कम से कम बना रहे;
- (ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हित लाभों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश रक्षित कर दे,
- (स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें;
- (द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिस्तर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे;
- (इ) शैक्षिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए,
10. दंड एवं हरजाना—
- (1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;
- (2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए— यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थान—
- (अ) ऐसे छात्र के विनोधाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे—पुस्तकालय, सभागार, आवासीय अगारों, गतागता, छात्रसंघ, भत्ते एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना;



Sd/-
VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tel. Wadwa. Dist. Sangli.

- (व) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश रशमित अथवा बाधित करना.
- (ख) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी.
- (ग) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना.
- (3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी बसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा:-
- (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;
- (ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;
- (स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;
- (द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
- (ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किरतों में किए जाने का औचित्य.

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाई:-

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य, धे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो यह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार राजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए.

12. गैर अनुपालन के परिणाम:-

- (1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक बिन्दुओं पर कार्यवाई करेगा:-
- (अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;
- (ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;
- (स) संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को चोक देना;
- (द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अमात्र घोषित किया जाना;
- (ई) जन साधारण को, एवं राजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त नीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अथवा जवसमतंदवम चवसपवलद का समर्थन नहीं करता है;
- (एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्यद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्यद्धता को आहरित करने की अनुशंसा के लिये करें




VC DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

- (जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केंद्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आह्वरण की अनुमति करना,
- (एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आह्वारित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथाचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;
- (जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन—III/4/असा/53]

जसपाल एस. संघु, सचिव, यूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent,
 - (b) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
 - (c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI.




V. C. SRINIVASAN
Venkateshwar Institute of Management
Path, Tel. Warwa, Dist. Sangli.

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASIH)) should be reconstituted as the ICC:
Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) "sexual harassment" means-
- (i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;-
- (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
- (b) demand or request for sexual favours;
- (c) making sexually coloured remarks
- (d) physical contact and advances; or
- (e) showing pornography"
- (ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
- (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
- (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
- (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
- (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;




I/C DIRECTOR
 Venkateshwara Institute of Management
 Peth, Tal. Waiwada, Dist. Sangli.

- (l) "student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI;
 Provided that a student who is in the process of taking admission in HEI's campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student;
 Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;
- (m) "third Party Harassment" refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose or reason;
- (n) "victimisation" means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;
- (o) "workplace" means the campus of a HEI including-
- Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;
 - Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;
 - Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIs.

3. **Responsibilities of the Higher Educational Institution-** (1) Every HEI shall,-

- Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;
- publicly notify the provisions against sexual harassment and ensure their wide dissemination;
- organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;
- act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;
- publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;
- reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;
- create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;
- include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual




VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tal. Wadgaon Dist. Sangli.

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC; Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 Supportive measures.—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.



[Signature]
Venkateswara Institute of Management
Peth, Tal. Wadwa, Dist. Sangli.

(6) All Academic Staff Colleges (now known as Human Resource Development Centres (HRDCs) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.

(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.

(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.

(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.

(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.

(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.

(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women's hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.

(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.

(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.

(15) The Women's Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitization and remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.

(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendments in the rules or Ordinances where necessary.

4. Grievance redressal mechanism.—(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-




VC DIRECTOR
 Venkateshvara Institute of Management
 Peth, Tal. Wotwa, Dist. Sangli.

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;"

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
- (2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
- (3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice- Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
- (4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
- (5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
- (6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
- contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
 - has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
 - he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
 - has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section."

5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) - The Internal Complaints Committee shall:
- provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;



SV
VC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management
 Peth, Tel. Mohad, Dist. Sangli.

- (b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;
- (c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender,
- (d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and
- (e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.

6. **The process for making complaint and conducting Inquiry** - The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy

7. **Process of making complaint of sexual harassment** - An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing:

Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period."

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental incapacity or death.

8. **Process of conducting Inquiry-** (1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.

(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.

(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.

(4) The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.

(5) An appeal against the findings or recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.

(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.

(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the




ICC DIRECTOR
 Venkateshwar Institute of Management,
 Peth, Tal. Wajra, Dist. Solapur

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. **Interim redressal**-The HEI may,

- (a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
- (b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
- (c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
- (d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
- (e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. **Punishment and compensation**- (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may:-

- (a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - (b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - (c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - (d) award reformatory punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
- (3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
- (a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - (b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - (c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - (d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - (e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. **Action against frivolous complaint**.—To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)




I/C DIRECTOR
 Venkateswara Institute of Management
 Peth, Tel. Warran, Dist. Sangli

of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

12. **Consequences of non-compliance.**—(1) The Commission shall, in respect of any institution that will fully contravenes or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice: -

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956;
- (b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (1) of section 2 of said Act, 1956;
- (c) withholding any grant allocated to the institution;
- (d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;
- (e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;
- (f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;
- (h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act.
- (i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations.
- (2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

[Advt -III/4/Exty.253]

JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC



VC DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Wajwa, Dist. Sangli.



DTE CODE - MB6224

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Grievance Redressal Cell

As per the Maharashtra Public University Act, 2016 of the State Government and as per the notices and office orders issued by the Shivaji University, Kolhapur, the college has established the Grievance and Redressal Cell. Before the Grievance and Redressal Cell, there was a Grievance and Redressal Committee which was formed at the beginning of every academic year and ensures the representation of all the stakeholders of the institute. As the College Management and the Administration strongly believes in Gandhian Philosophy of Education, they ensure a secular, all-inclusive and secure atmosphere on the campus. Grievance and Redressal Cell conducts a mechanism of grievance redressal of students and prevention of sexual harassment and ragging of students. At the beginning of every academic year a meeting of staff and students were conducted by the Director to make the new students acquainted with the mechanism.

Grievance Redressal Committee objectives

- 1) The primary objective of the GRC is to ensure a fair and impartial resolution of grievances. It is responsible for examining complaints without bias and providing equitable solutions.
- 2) The committee aims to promptly address and resolve grievances raised by employees, customers, clients, or any other stakeholders related to the organization's operations.
- 3) One of the key objectives is to mediate and resolve conflicts or disputes that may arise between different parties involved with the organization.
- 4) The GRC ensures that the organization complies with all applicable laws, regulations, and internal policies related to grievance handling.

Function of Grievance Redressal Cell:

The functional mechanism of working of Grievance Redressal Cell is as the prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012 and Maharashtra Public University



IC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



DTE CODE - MB6224

SHRI VENKATESHWARA SHIKSHAN SANSTHA'S

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MANAGEMENT (M.B.A.)

GAT NO. 2665, PETH NAKA, TAL. WALWA, DIST. SANGLI. (MH) 415 407

PH. NO. (02342) 252100, 252110

Act, 2016 as it came in force. All the rules and regulations prescribed by the competent authority will be followed.

Jurisdiction of Grievance Redressal Cell

- a) The complaints regarding the admission and fees
- b) The complaints regarding the ragging and sexual harassment (the separate mechanism for these issues is also in force, but in the grave event handed over to the cell)
- c) The complaints regarding the academic and administrative processes
- d) The complaint against any staff member regarding academic and personal issues
- e) The complaints regarding examinations, results and scholarship

Mechanism of Grievance Redressal Cell:

- a) The grievances can be filed orally and in a written format to the Director or if the aggrieved student wants to keep his identity secret, he/she can put his complaint through the blind Complaint/Suggestion Box kept outside the Office.
- b) The Complaints registered directly to the Director is noted down in a separate complaint lodge book, which is kept in the custody of the Subrident of the office.
- c) The Complaint/Suggestion box is opened in the presence of any one member of the Cell and then registered in the complaint lodge book.
- d) After the judicious inquiry and statements from both the parties and the teachers and other related persons, the Grievance Cell will assure that the grievance has been properly solved in a stipulated time limit.
- e) The complaints that require the attention of the higher authorities and local police station, will be addressed only with their help.




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's

Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Internal Complaints Committee

The Internal Complaints Committee (ICC) is an essential entity established in organizations to address and resolve complaints related to sexual harassment at the workplace. Its primary objectives are to create a safe and respectful work environment for all employees, regardless of gender, and to ensure that any complaints of harassment are promptly and fairly dealt with. Here are the main objectives of an Internal Complaints Committee.

As per the guidelines of Supreme Court, UGC, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been established by the College for a period of five years (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22). A victim of sexual harassment has two courses open in having her grievance redressed. She can either give a complaint to the Internal Complaints Committee or give a police complaint relating to the penal offence.

Preamble

The Parliament of India passed the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act," in the year 2013. The ACT provides protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for the matters connected therewith or incidental thereto. The guidelines explicitly state the following: "It shall be the duty of the employer or other responsible persons in workplaces or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolutions, settlement, or prosecution of acts, of sexual harassment by taking all steps require."

Educational institutions are also bound by the Supreme Court's directive and the Act. The International Institute for Population Sciences (IPS), Mumbai is committed to creating and maintaining an environment which is free of all forms of gender violence, sexual harassment, and discrimination on the basis of sex/gender. Following this, the institute is "Internal Complaint Committee to Prevent Sexual Harassment of Women at the Workplace.



Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tst. Walva, Dist. Sangli.

Objectives of Internal Complaints Committee:-

- 1) The primary objective of the ICC is to prevent incidents of sexual harassment within the workplace. By implementing policies and guidelines, conducting awareness programs, and providing training to employees, the ICC aims to create a safe and harassment-free environment.
- 2) The ICC acts as a confidential and safe platform for employees/students to report any incidents of sexual harassment they may experience or witness. It ensures that complainants are not victimized or subjected to retaliation for reporting such incidents.
- 3) One of the core responsibilities of the ICC is to investigate complaints of sexual harassment thoroughly and impartially. The committee is entrusted with gathering evidence, interviewing witnesses, and making recommendations based on the findings of the investigation.
- 4) The ICC aims to resolve complaints of sexual harassment promptly and fairly. This includes providing a fair hearing to both the complainant and the accused, and ensuring that due process is followed throughout the proceedings.

The Definition of Sexual Harassment

According to THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT 2013, sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:

1. Physical contact and advances;
2. A demand or request for sexual favours;
3. Making sexually colored remarks;
4. Showing pornography,
5. Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Sexual harassment and punishment for sexual harassment

A man committing any of the following acts-

Physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures: or a demand or request for sexual favours, or showing pornography against the will of a woman or making sexually coloured remarks, shall be guilty of the offence of sexual harassment.




ICC DIRECTOR
Venkateshvara Institute of Management
Peth, Tal. Waiwa Dist. Sangli.

Any man who commits the offence specified in clause (3) or clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both.

Prevention of sexual harassment (Section 3):

(1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace:-

(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment

- (i) Implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or
- (ii) Implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment or
- (iii) Implied or explicit threat about her present or future employment status; or
- (iv) Interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, or
- (v) Humiliating treatment likely to affect her health or safety.

In the event the Committee finds that the allegation(s) against the respondent have been proved, it shall recommend the nature of action to be taken by the Institute.

Internal Complaints Committee (ICC):

An aggrieved woman can send a written complaint to the Director of the Venkateshwara Institute of Management, Peth. The said complaint shall be forwarded to the Internal Complaints Committee (ICC) for an inquiry.

This committee has been formed at Venkateshwara Institute of Management, Peth, to address issues under THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013. The purpose of this committee is to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding five years, from the date of nomination.




VC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Wankar, Dist. Sangli.

Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha's
Venkateshwara Institute of Management (M.B.A.)

Anti-Ragging Committee

Introduction

The College has constituted the Anti-Ragging Committee in the year 2012-13. The following instructions are framed to prevent the menace of ragging and foster healthy interpersonal relations among students in the campus of Venkateshwara Institute of Management Peth. Ragging is strictly forbidden in or outside the college campus. All students shall familiarize themselves with rules/regulations/guidelines on code of conduct anti-ragging measures and discipline College. All 'new comers' should attend counseling sessions organized for them from time to time by the college staff.

Objectives:-

- 1) The committee works to prevent ragging incidents from occurring in the first place. It raises awareness among students about the consequences of ragging and the college's strict stance against it.
- 2) The committee educates students about the negative impacts of ragging on victims' mental and emotional well-being, as well as the legal implications for those involved in ragging incidents.
- 3) The committee develops clear and comprehensive anti-ragging policies and guidelines that outline what constitutes ragging, the penalties for engaging in it, and the reporting mechanisms.
- 4) Upon receiving reports of ragging or any related incidents, the committee takes prompt action to investigate the matter thoroughly. It ensures that disciplinary actions are taken against those found guilty, in accordance with the college's policies.



Functions of Committee:-

- 1) The committee develops and updates comprehensive anti-ragging policies and guidelines that define what constitutes ragging, the penalties for engaging in it, and the reporting mechanisms. These policies are communicated to all students and staff members.
- 2) The committee conducts orientation programs for newly admitted students to educate them about the college's policies on ragging, its consequences, and the support mechanisms available to them.
- 3) The committee keeps a vigilant eye on the campus to detect any potential ragging activities. This involves regular inspections and interactions with students to ensure a safe atmosphere.
- 4) The committee establishes a system for students, faculty, and staff to report any incidents or suspicions of ragging. It thoroughly investigates these reports while maintaining the confidentiality of the complainants.

Anti-Ragging Rules and regulations:

- 1) Ragging is prohibited as per Act-26 of A.P. Legislative Assembly. 1997.
- 2) Ragging entails heavy fines or imprisonment.
- 3) All the student must carry their identity cards & show them when demanded.
- 4) Outsider are prohibited from entering the college without permission.

Sexual Harassment rules:

- 1) Provide a safe working environment at the college/workplace.
- 2) Treat sexual harassment as misconduct under the service rules & initiate action.
- 3) Forming an Internal Complaint Committee (ICC) at college.
- 4) ICC must observe the implementation of Anti-Sexual Harassment at College & recommend disciplinary actions if any to the employer's students



P. K. Kulkarni
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.



घान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax: 011-2323 8858

E-mail: secy.ugc@nic.in

D. O. No. F. 3-2/2021 (ARC)

27 OCT 2021 October, 2021

'SPEED POST'

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, in pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" and in compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, **www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**.

As part of UGC's initiative towards reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (**www.antiragging.in** and **www.amanmovement.org**) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the regulations on curbing the menace of ragging. He/She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (Step 1 is the same like before).

Step 2: The student will receive an E MAIL with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the E mail of the Nodal officer in his/her university/college. **(Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case earlier).**

Step 3: The Nodal Officer in the university/college can click on the link of any forwarded e mails that he/she will receive from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

Contd.../-




UGC DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Post, Tal. Warwa, Dist. Sangli

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.
(Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)
New Delhi-110002, the 17th June 2009

F.1-16/2007(CPP-II)

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SUP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student-or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause-(g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;




I/C DIRECTOR
Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment .or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it



under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary-course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.



4. Definitions.-

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires, -
- a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
 - c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.
 - d) "Commission" means the University Grants Commission;
 - e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
 - f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
 - g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
 - h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
 - i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.



j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act; .

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus, or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any Institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution.



and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any



other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.

f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.

h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,



parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.

l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.

m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.

n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.

o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available



when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

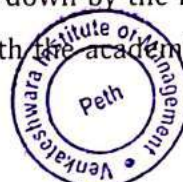
6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities?

b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted o the institution in earlier years.

c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden *or* to the Head of the institution, as the case may be.

d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.



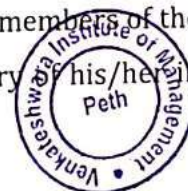
e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.

f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.

g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.



- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
- k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the Institution.
- l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
- m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year,
- n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.
- o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
- p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.



q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members; representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender,

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution.



or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person; as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1,

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry .. observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

f) Every institution shall, at the end of each academic year, In order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.

h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.



6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the dose vicinity thereof.
- b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among ail students residing in the hostel.
- c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
- d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
- e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
- f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
- g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards



and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice,

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record,

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been



punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution,

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor or each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;



- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils. -

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;



a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.

b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.

c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.

d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.

e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;



- a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.
- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.
- f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency



responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging,-

9.1 The institution shall punish student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

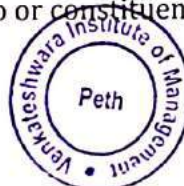
a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.

b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;

- i. Suspension from attending classes and academic privileges.
- ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
- iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process,
- iv. Withholding results.
- v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- vi. Suspension/ expulsion from the hostel,
- vii. Cancellation of admission.
- viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters,
- ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

- c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,
- i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;



- ii. in case of an order of a University, to its Chancellor.
- iii. in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

- i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.
- ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies,

- iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any
- iv. Withholding any grants channelised through the university to the institution,
- v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary



action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps " to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one or more of the following measures, namely;

- i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
- ii. Withholding any grant allocated,
- iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
- iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
- v. Taking such other action within its-powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.

(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary



ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, _____ (Full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having been admitted to _____ (name of the institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the regulations and am aware as to what constitutes ragging

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that
a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

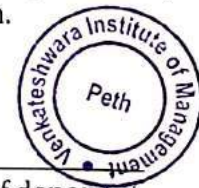
Declared this ___ day of _____ month of ___ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).



Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, _____ full name of student with admission/registration/enrolment number _____, having been admitted to _____ (name of the institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the regulations and am aware as to what constitutes ragging

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of _____ month of ___ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

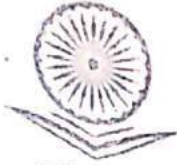
Verified at ___ (place) ___ on this the ___ (day) of ___ (month) ___, ___ (year) ___.



Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ___ (day) of ___ (month) ___, (year) ___ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



मानव-संसाधन विकास

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No. 14-4/2012(CPP-II)

7th December, 2018

PUBLIC NOTICE

ON

UGC (GRIEVANCE REDRESSAL) REGULATIONS, 2018

UGC had notified UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012 in official Gazette of India on **23rd March, 2013**. These regulations were aimed at addressing and effectively resolving grievances of students related to Higher Educational Institutions.

The UGC had received a number of responses on these regulations and hence constituted an Expert Committee to revisit UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012. The draft University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018 prepared by the Committee is attached herewith for observations and suggestions of stakeholders. The feedback and comments on the above draft may be sent to UGC via email grmhei.2018@gmail.com on or before **31st December, 2018**.

(Prof. Rajnish Jain)



P. K. Kulkarni
DIRECTOR

Venkateshwara Institute of Management
Peth, Tal. Walwa, Dist. Sangli.

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002**

NOTIFICATION

F.No.14-4/2012 (CPP-II)

New Delhi, the __ October, 2018

In exercise of the power conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018.
- b) They shall apply to all HEIs, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations, and includes a person seeking admission to any institution of higher education;
- (c) "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any



qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

(d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.

(e) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub-regulation (1) of regulation 3;

(f) "grievances" include the following complaints of the aggrieved students, namely:

- i. making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
- ii. irregularity in the admission process adopted by the institution;
- iii. refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institution;
- iv. non publication of prospectus, (either hard copy / online) as specified in these regulations;
- v. publishing any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
- vi. withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a students for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
- vii. demand of money in excess of that specified in the declared admission policy to be charged by such institution;



- viii. breach in reservation policy in admission as may be applicable;
 - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority;
 - x. delay in conduct of examinations or declaration of results beyond the specified schedule in the academic calendar;
 - xi. on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
 - xii. non transparent or unfair evaluation practices;
 - xiii. Refund of fees, in case a student withdraws the admission within the stipulated time as mentioned in the prospectus, as notified by the Commission from time to time.
- (g) "Department Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department.
- (h) "Institutional Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of an Institution.
- (i) "College Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a college.
- (j) "University Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a University.
- (k) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1956;
- (l) "Institution" for the purposes of these regulations, means any university, college or such other institutions, as the case may be;
- (m) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached;



(n) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;

(o) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.

3. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

i. Every higher educational institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:

(a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;

(b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

(c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;

(d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;



- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules / regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular / visiting ---- and teaching experience of every member of its teaching faculty.
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution.
- (k) any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish / upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

- ii. Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its



publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (GRC):

A. Department Grievance Redressal Committee (DGRC)

- (i) In case of universities, all complaints relating to a department shall first be addressed to Department Grievance Redressal Committee (DGRC) to be constituted at the level of departments/school/center whose composition shall be as follows:
 - a) Head of the Department / School / Center – Chairperson
 - b) a Professor from outside the department / school / center to be nominated by the Head of HEI – Member
 - c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the Department – Member.
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.
- (v) The DGRC shall make efforts to resolve the grievance within the stipulated period and shall submit its report to the Head of the Institution within a period of 15 days from the date of receipt of complaint to the DGRC.
- (vi) The DGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

B. Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC)



- (i) The complaints not related to departments/schools / center and the grievances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC) to be constituted by Head of the HEI, whose composition shall be as follows:
 - (a) Pro-Vice Chancellor / Dean/ Senior academician of HEI – Chairperson.
 - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare
 - (c) Two senior academicians other than Chairperson.
 - (d) Proctor / Senior academician
- (ii) The above Committee shall be approved by the statutory body of institution (Executive Council or its equivalent).
- (iii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Committee members shall be two years.
- (iv) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.
- (v) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while giving its recommendations. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.
- (vi) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.
- (vii) The IGRC shall send the report and the recommendations to the Head of the HEI within in a period of 15 workings days from the date of receipt of grievance, or appeal or recommendations of the DGRC.
- (viii) The IGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

C. College Grievance Redressal Committee (CGRC)



- (i) In case of colleges, all complaints shall first be addressed to College Grievance Redressal Committee (CGRC) whose composition shall be as follows:
 - a) Principal of the college -Chairperson
 - b) Two senior faculty members nominated by the principal of the College.
- (ii) The tenure of the members shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and recommendations to the Vice-Chancellor of the affiliating university within a period of 15 days of receiving the complaint.

D. University Grievance Redressal Committee (UGRC)

- (i) In case of grievances not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Committee (UGRC) for which the Vice-chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Committee (UGRC) consisting of five members for a individual colleges or a group of colleges keeping in view the location of the college(s). The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the affiliating university consisting of :
 - a) A senior Professor of the university – Chairperson
 - b) Dean, Student Welfare or its equivalent - Member
 - c) Three Principals drawn from the affiliating colleges, on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor – Members
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.



(iv) The CGRC shall follow the principle of normal justice while deciding the grievance of the students.

(v) The CGRC shall send the report and the recommendations to the principal of the college within a period of 15 days of receiving the complaint.

E. Any person aggrieved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Committee or University Grievance Redressal Committee may within in a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

5. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each HEI shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students under these regulations.

(ii) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a retired Vice-Chancellor, Registrar or a faculty member who has at least ten years of experience as a Professor.

(iii) The Ombudsperson shall not be in any conflict of interest with the university, either before or after his appointment.

(iv) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not -

(a) hold or have held at any point in the past, any post or, employment in any office of profit in the university;

(b) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;

(c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.

(v) The Ombudsperson in a State University shall be appointed by the Executive council of the university on part-time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-



- (a) Nominee of the Governor of the State or his nominee - Chairperson
 - (b) Vice-Chancellor of a University of State to be nominated by the State Government – Member
 - (c) Vice-Chancellor of the concerned State University – Member
 - (d) Registrar of the concerned State University – Secretary (non-voting)
- (vi) The Ombudsperson in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Executive Council of the Central University or the equivalent statutory body of the Deemed to be University, as the case may be, on part - time basis from a panel of three member recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of University Grants Commission -- Chairperson,
- (b) One Vice Chancellor from Central University to be nominated by UGC (for Central Universities) – Member

OR

One Vice Chancellor from institution deemed to be university to be nominated by the UGC (for Deemed to be Universities) - Member

- (c) The Vice Chancellor of the university – Member
 - (d) The Registrar of the university – Secretary (Non-Voting)
- (vii) The Ombudsperson shall be a part time officer appointed for a period of three years from the date he/she assumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
- (viii) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as per the norms of the university for hearing the cases, in addition to the reimbursement of the conveyance.



- (ix) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under these regulations, by the concerned appointing authority i.e. the Executive Council of the University.

6. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear any appeal of an applicant for admission as student or student of the university against the university or institution affiliated to it as the case may be, after the student has availed all remedies available in such institution for redressal of grievance such as IGRC / UGRC;
- (ii) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, the issues of malpractices in the examination and evaluation processes may be referred to the Ombudsperson.
- (iii) Ombudsperson may seek the assistance of any person as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the student(s).

7. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSON AND GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that institution may submit an application seeking grievance redressal.
- (ii) On receipt of any online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Committee, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.
- (iii) The Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved person.



- (iv) An aggrieved person may appear either in person or be represented by such person as may be authorized to present his/her case.
- (v) The Grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Committee(s) shall be referred to the Ombudsperson.
- (vi) The institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Vice Chancellor.
- (vii) On the conclusion of proceedings, the Ombudsperson shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.
- (viii) Every order under the signature of the Ombudsperson shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. Any recommendations of the Ombudsperson not complied with by the institution shall be reported by the Ombudsperson to the Commission.
- (x) In case of any false or frivolous complaint, the Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant.

8. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSON GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

The institution shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee(s) and Ombudsperson on their website and in their prospectus prominently.

9. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal



Committee(s), as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) The Commission may take necessary and appropriate action as it may deemed fit, in case of an institution deemed to be university;
- (g) recommend to the concerned State Government for necessary and appropriate action, in case of a university established or incorporated under a State Act;
- (h) The Commission may take necessary and appropriate actions against any institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

(Prof. Rajnish Jain)
Secretary

